RNI No. DELMUL/2012/47011

26 जुलाई, 2026 रविवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 115

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

मध्यप्रदेश के 4 महानगरों में प्रारंभ होंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट : सीएम 08

संक्षिप्त वार्ता

भारी बारिश में गुजरात के कई जिले हुए जलमग्न

नई दिल्ली। भारी बारिश से गुजरात में कई जिले जलमग्न हैं। नॉर्थ गुजरात और साउथ गुजरात में तेज बारिश हो रही है। बनासकांठा जिले के देवदार तालुका में सबसे ज्यादा 1.85 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। लखनी में 1.73 इंच, धनेरा में 1.46 इंच और राह तालुका में 1.42 इंच बारिश हुई। ओड में 1.30 इंच, वलसाड जिले के नानापोंधा में 1.22 इंच और नवसारी जिले के खेरगाम में 1.02 इंच बारिश दर्ज की गई। बनासकांठा, पाटन, और कच्छ जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान और 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही बिजली कड़कने की भी आशंका है।

भोपाल में 30 हजार कारोबारियों पर कार्रवाई की तैयारी

भोपाल, वेब वार्ता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। पहले चरण में 429 दुकानों, कार्यालयों, बैंकों और शोरूमों को नोटिस जारी किए गए हैं। नगर निगम का अनुमान है कि शहर में करीब 30 हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान नियमों के विपरीत संचालित हो रहे हैं। इस बीच भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व्यापारियों के समर्थन में खुलकर सामने आया है और कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

नगर निगम ने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 और नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 के तहत नोटिस जारी कर संबंधित प्रतिष्ठानों को 27 जुलाई तक वैध अनुमति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज नहीं देने या अवैध व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं करने पर सीलिंग की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में की जा रही है। निगम को 30 जुलाई तक कोर्ट में शपथ-पत्र दाखिल करना है, जबकि मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को प्रस्तावित है।

भीम आर्मी का प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

सागर, वेब वार्ता। मध्य प्रदेश के सागर में शनिवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। चंद्रा पार्क से निकाली गई रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार प्रतीक श्रीवास्तव को सौंपा गया।

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और युवा शामिल हुए। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचने पर कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब कुछ प्रदर्शनकारी प्रवेश द्वार पर लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ गए। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई और प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।

रैली में शामिल लोगों के हाथों में विभिन्न मांगों से संबंधित बैनर और तख्तियां थीं। एक पोस्टर पर लिखा संदेश मुर्दों का शहर मध्यप्रदेश और चमचों का शहर सागर भी चर्चा का विषय बना रहा। प्रदर्शन में नर्सिंग विद्यार्थियों ने भी भागीदारी की। उन्होंने समय पर परीक्षाएं आयोजित कराने और लंबित छात्रवृत्ति शीघ्र जारी करने की मांग उठाई।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जंतर-मंतर में जश्न

अभिजीत दीपके ने बताया आंदोलन की पहली जीत

नई दिल्ली, वेब वार्ता

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के बाद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद छात्र-युवाओं ने नारे लगाए, नृत्य किया और इसे अपने आंदोलन की पहली बड़ी सफलता बताया। इस दौरान पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का भावुक क्षण भी चर्चा का विषय बना।

सामाजिक माध्यम पर प्रसारित वीडियो में अभिजीत दीपके को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सूचना मिलते ही मंच पर भावुक होते देखा गया। वीडियो में वह घुटनों के बल बैठकर मंच पर हाथ मारते हुए खुशी व्यक्त करते दिखाई देते हैं। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद समर्थकों ने भी नारेबाजी कर इस घटनाक्रम का स्वागत किया। जंतर-मंतर से जनपथ तक कई स्थानों पर छात्र और युवा जश्न मनाते दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से चल रहे आंदोलन का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना था और इस्तीफे को उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

अभिजीत दीपके ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक संघर्ष की पहली जीत है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों को भयभीत होने के बजाय अपनी बात निर्भीकता से रखनी चाहिए। उनके अनुसार, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से चलाए गए आंदोलन ने यह सिद्ध किया है कि जनदबाव के माध्यम से भी परिवर्तन संभव है। उन्होंने कहा कि आंदोलन की अन्य प्रमुख मांगें अभी भी लंबित हैं। इनमें नीट परीक्षा विवाद के दौरान आत्महत्या करने वाले छात्र-छात्राओं के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान छात्रों के विरुद्ध हुई कथित कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग शामिल है।

शेष पृष्ठ 3 पर...

धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, नीट विवाद और छात्र आंदोलन के बीच बड़ा फैसला

नई दिल्ली, वेब वार्ता

जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक मामले में देशभर के छात्र पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। जंतर-मंतर पर आंदोलन में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे। छात्रों की पहली डिमांड शिक्षा मंत्री प्रधान का इस्तीफा थी। प्रधान ने शनिवार दोपहर को मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया।

उन्होंने कहा, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

शेष पृष्ठ 3 पर...

पाकिस्तान में आतंकी हमला, 15 सुरक्षाकर्मियों की मौत

वेब वार्ता, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टांक जिले में संयुक्त पुलिस जांच चौकी पर हुए भीषण आतंकी हमले में 12 सैनिकों समेत कम से कम 15 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। मृतकों में दो पुलिसकर्मी और वन विभाग का एक कर्मचारी भी शामिल है।

सेना की मीडिया शाखा के अनुसार प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े आतंकियों ने तड़के सुरक्षा घेरा तोड़कर चौकी में घुसने की कोशिश की। सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भागते समय आतंकियों ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी चौकी की बाहरी दीवार से टकरा दी, जिससे जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट में 15 सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई और चौकी की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। हमले के तुरंत बाद सुरक्षाबलों ने आतंकियों का पीछा किया और मुठभेड़ में 12 आतंकवादियों को मार गिराया। अधिकारियों के अनुसार पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और फरार आतंकियों की तलाश के लिए व्यापक तलाशी अभियान जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 862 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स

पेपर लीक मामलों का निपटारा भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में

वेब वार्ता, नई दिल्ली

पेपर लीक से जुड़े मामलों का निपटारा अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा। पीएम मोदी ने खुद इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामलों में शामिल लोगों को जल्द और सख्त सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए और मामले के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार के मुताबिक मजबूत कानून के बावजूद देश भर की अलग-अलग कोर्ट में रेप और पॉक्सो एक्ट के कई मामले पेंडिंग हैं। कड़ी सजा का मकसद लोगों में डर पैदा करना है लेकिन यह तभी हो सकता है जब ट्रायल तय समय पर पूरा हो और पीड़ितों को जल्द इंसाफ मिले। सबसे पहले 11वें वित्त आयोग ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सिफारिश की थी। पहली बार साल 2000 में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी थी।

बता दें 14वें वित्त आयोग ने 2015-2020 के दौरान देशभर में 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की सिफारिश की। इनका मकसद गंभीर अपराधों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और 5 साल से ज्यादा पेंडिंग संपत्ति से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई करना था। वित्त आयोग ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वे टैक्स से मिलने वाले ज्यादा फंड का इस्तेमाल इस काम के लिए करें। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो से जुड़े मामलों के जल्द से जल्द निपटारे करने का निर्देश दिया। इसके बाद केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाने की स्कीम शुरू की, जिसके तहत रेप और पॉक्सो से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए देशभर में स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए।

...जहाँ 105 ऐसी अदालतें हैं

इस स्कीम के तहत ऐसे मामलों के ट्रायल के लिए एफटीएससी बनाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों की मदद करती है। स्कीम के तहत एफटीएससी बनाने के लिए केंद्र सरकार 60फीसदी पैसा देती है, जबकि बाकी का 40फीसदी राज्यों को लगाना होता है। केंद्र सरकार ने संसद में कुछ आंकड़े दिए थे। 27 मार्च 2026 को लोकसभा में कानून मंत्रालय ने बताया था कि 31 जनवरी 2026 तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 862 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। सबसे ज्यादा 373 एफटीसी उत्तर प्रदेश में हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 105 ऐसी अदालतें हैं।

स्वदेशी काउंटर-ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का ट्रायल सफल, दुश्मन के ड्रोन को हवा में करेगा नष्ट

वेब वार्ता, नई दिल्ली

भारतीय सेना के सामने सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड ने नागपुर में अपने स्वदेशी काउंटर-ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल लाइव ट्रायल किया। कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम हवाई हमलों और ड्रोन के झुंड जैसे बढ़ते खतरों से निपटने के लिए तैयार है। इसे सेना के कमांड और कम्युनिकेशन नेटवर्क सी4आई से भी जोड़ा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक यह सिस्टम खतरनाक ड्रोन और खुद से उड़ने वाले ड्रोन के झुंड को रोकने के लिए बनाया गया है। इनपुट में ट्रायल की तारीख और सेना की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया की जानकारी नहीं दी गई है। यह जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कंपनी के मुताबिक ट्रायल सफल रहा।

भार्गवास्त्र को गाड़ी पर आसानी से लगाया जा सकता है। इससे जरूरत पड़ने पर इसे दूसरी जगह ले जाकर तैनात भी किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि इससे अलग-अलग इलाकों में तुरंत ऑपरेशन करना आसान होगा। कंपनी के मुताबिक इस सिस्टम में देश में बने रॉकेट और सटीक निशाना लगाने वाली माइक्रो-मिसाइल लगी हैं। दावा किया कि ये दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकती हैं।

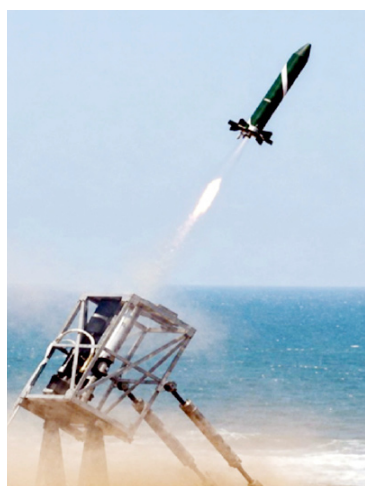

ट्रैक करने में करते हैं मदद

मीडिया रिपोर्ट में कंपनी के हवाले से बताया कि भार्गवास्त्र को रेगिस्तान, मैदान और समुद्र तल से 5,000 मीटर तक ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है। इसे अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों में इस्तेमाल करने के हिसाब से तैयार किया गया है। सिस्टम के कंट्रोल सेंटर में 10 किमी तक ड्रोन का पता लगाने वाला रडार और खास सेंसर लगाए गए हैं। कंपनी के मुताबिक ये सेंसर लक्ष्य की पहचान कर उसे ट्रैक करने में मदद करते हैं, जिससे ड्रोन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

होर्मुज स्ट्रेट के पास एलपीजी टैंकर पर हमला

28 भारतीय थे सवार, सभी सुरक्षित

वेब वार्ता, तेहरान। ईरान के जलक्षेत्र में एक एलपीजी टैंकर पर हमला हुआ। जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि वह संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। भारतीय दूतावास ने एक्स पर जारी बयान में बताया कि मोजाम्बिक के झंडे वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर हमला हुआ, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित हैं।

मीडिया रिपोर्ट में भारतीय समुद्री कर्मचारियों के संगठन फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया के मुताबिक यह हमला शुक्रवार को होर्मुज स्ट्रेट के पास एक अज्ञात

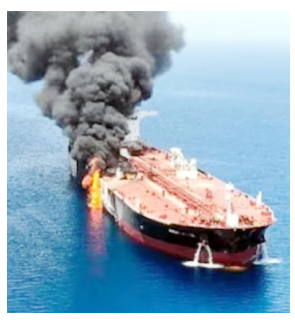

मिसाइल से किया गया। उस समय टैंकर फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहा था। हालांकि, हमले के पीछे किसका हाथ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस घटना ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। ईरान और ओमान के बीच स्थित यह जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। हालिया संघर्ष से पहले दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ने के बाद इस इलाके में समुद्री गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। जुलाई की शुरूआत में दोनों देशों के बीच बना अस्थायी युद्धविराम टूटने के बाद हमलों और जवाबी हमलों का दौर फिर शुरू हो गया, जिससे होर्मुज स्ट्रेट में व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

मध्य प्रदेश में 20 आईएएस अफसरों के तबादले, 6 जिलों के कलेक्टर बदले

राजौरा बने प्रशासन अकादमी के डीजी, डॉ. खाड़े मुख्यमंत्री के सचिव नियुक्त

वेब वार्ता, भोपाल

मध्य प्रदेश सरकार ने अशोक वर्णवाल के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने के महज 24 घंटे के भीतर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आधी रात को 20 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल के तहत 6 जिलों में नए कलेक्टरों की तैनाती की गई है, वहीं इंदौर संभागायुक्त और मुख्यमंत्री सचिवालय समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के शीर्ष अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शुक्रवार देर रात जारी आदेश के अनुसार, इंदौर के संभागायुक्त डॉ. सुदाम पी. खाड़े को मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है, जबकि उनकी जगह भास्कर लक्षकार को इंदौर का नया संभागायुक्त बनाया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मण्डलोई को जनवरी 2027 में भोपाल में आयोजित होने वाली 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' (जीआईएस) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके साथ ही

उन्हें औद्योगिक नीति एवं एमएसएमई विभाग का दायित्व भी दिया गया है। इसके अलावा, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा को प्रशासन अकादमी का महानिदेशक (डीजी) नियुक्त किया गया है।

6 जिलों में नए कलेक्टरों की नियुक्ति

प्रशासनिक बदलावों के तहत रतलाम, शहडोल, अनूपपुर, खरगोन, मंदसौर और आगर मालवा में नए कलेक्टरों की नियुक्ति की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग में पदोन्नति नियम-2025 और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले अपर सचिव अजय कटेसरिया को रतलाम का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं शहडोल में मिशा सिंह, अनूपपुर में रत्नाकर झा, खरगोन में गुरु प्रसाद, मंदसौर में दिव्यांक सिंह और आगर मालवा में डॉ. शेर सिंह मीना को जिले की कमान सौंपी गई है। खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल के दो वर्ष की स्टडी लीव पर जाने तथा मंदसौर व आगर मालवा की निवर्तमान कलेक्टरों को भोपाल स्थानांतरित किए जाने के बाद यह नई पदस्थापनाएं की गई हैं। इन बदलावों के बाद प्रदेश में महिला कलेक्टरों की संख्या 17 से घटकर 15 रह गई है।

फेरबदल में संदीप यादव को जल संसाधन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है, जिसके तहत वे केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध नदी जोड़ो परियोजनाओं का काम देखेंगे। नर्मदा घाटी विकास (एनवीडी) का प्रभार राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ई. रमेश कुमार को सौंपा गया है। वहीं, सचिन सिन्हा को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है और मनीष सिंह को ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पिछले ढाई वर्षों से औद्योगिक नीति संभाल रहे राघवेंद्र सिंह को वन विभाग का प्रमुख सचिव बनाते हुए आनंद विभाग का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है, जबकि कुमार पुरुषोत्तम को मंडी बोर्ड के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

संपादकीय

शर्तों की मोहताज संसद

संसद के मानसून सत्र के पांच दिन बीत चुके हैं। कोई काम नहीं, कोई चर्चा नहीं, सिर्फ हंगामा और नारेबाजी! संसदीय व्यवस्था के अनुसार, 45 करोड़ रुपए से अधिक फुंक चुके हैं। यह किसी सरकार, विपक्ष या आंदोलनकारी की राशि नहीं थी। करदाता ने दी थी, ताकि संसद चल सके। संसद के पटल पर सिर्फ वे कागजात या रपटें रखी जा सकी हैं, जिनकी औपचारिकता विधायी तौर पर अनिवार्य होती है। स्पीकर, सभापति और पीठासीन अधिकारी आसन पर आकर बैठते हैं, विपक्ष के हंगामा करते सांसदों को उपदेश देते हैं, अंततः सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ती है। विपक्ष और प्रदर्शनकारी बखूबी जानते हैं कि यदि वर्फ पिघलेगी और कोई समाधान निकलेगा, तो वह सिर्फ और सिर्फ संसद में चर्चा के बाद ही निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार, 23 जुलाई, देर रात फास्ट ट्रैक कोर्ट बिल के मसविदे की घोषणा की है और शिक्षा मंत्रालय के दो शीर्ष, सचिव स्तर के अधिकारियों के तबादले किए हैं। अब कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विधेयक संसद में आना है। संसद में ही उसे पारित किया जा सकता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह कानून बन सकता है। यदि संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का बिल और माफिया को जल्द और कठिन दंड और असंभव-सी जमानत वाला कानून लटक कर रह जाएगा। सड़कों पर नारेबाजी और हुड़दंग मचाने से कोई भी विधायी व्यवस्था नहीं बन सकती। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और लगभग समूचे विपक्ष की यह शर्त है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए अथवा प्रधानमंत्री उन्हें बर्खास्त करें। उसके बाद ही संसद में चर्चा संभव है। जंतर-मंतर पर बीते 35 दिनों से प्रदर्शन कर रहे युवाओं की भी यही शर्त है।

बहरहाल हर सड़किया प्रदर्शनकारी की शर्तों के मुताबिक, न तो संसद चलती है और न ही बहस की दिशा और आधार तय होते हैं। इस देश में संसद और आंदोलनकारी दोनों ही स्वतंत्र हैं। शुक्रवार, 24 जुलाई, की सुबह एक सुखद खबर मिली कि देर रात करीब 12.40 बजे सोनम वांगचुक ने 26 दिन से जारी अपना अनशन तोड़ दिया। केंद्रीय मंत्रियों-जेपी नड्डा और डॉ. जितेन्द्र सिंह-ने मेदांता अस्पताल जाकर उन्हें जूस पिलाया और यूं वांगचुक का अनशन टूटा। अब उन्हें प्रदर्शन कर रहे युवाओं का आह्वान करना चाहिए कि आंदोलन समाप्त करो, सरकार के आश्वासन पर भरोसा कर कुछ समय दो, लेकिन वांगचुक ने ऐसा नहीं किया है, हालांकि आंदोलनरत कॉकरोचों ने अनशन तोड़ने को बड़ी राहत माना है। बहरहाल शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की शर्त वांगचुक और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नहीं है। वे बेहतर शिक्षा-व्यवस्था और पेपरलीक सरीखे राष्ट्रीय मुद्दे पर संसद के भीतर सकारात्मक चर्चा के पक्षधर हैं। मंत्री का इस्तीफा तो कभी भी हो सकता है, लेकिन सरकार के विरोध में सबसे बुलंद और शर्तनुमा आवाज राहुल गांधी की है, क्योंकि उनके पास कांग्रेस के 98 सांसदों का समर्थित समर्थन है। विपक्ष की भी मजबूरी है कि उनके साथ ही चले। नतीजा यह है कि संसद विभिन्न पक्षों की शर्तों की मोहताज लग रही है। संसद में कई-कई दिन लंबे हंगामे और गतिरोध तब भी होते थे, जब भाजपा विपक्ष में थी, लेकिन महिला आरक्षण सरीखे बेहद संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व के बिलों, मुद्दों पर भाजपा ने कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को समर्थन भी दिया था। क्या अब अपेक्षा की जानी चाहिए कि सोमवार, 27 जुलाई, या उसके बाद जब भी प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि वाला फास्ट ट्रैक कोर्ट बिल संसद में पेश किया जाएगा, तो विपक्ष उसे पारित कराने में सहयोग करेगा? लेकिन एक और भयानक चुनौती देश देख-महसूस कर रहा है कि युवा, हम छात्र कहने की गलती नहीं कर सकते, आंदोलित और आक्रोशित होने के बाद अब चाकूबाज, पत्थरबाज के तौर पर हिंसक भी होता जा रहा है। वांगचुक ने भी माना है कि आंदोलन, प्रदर्शन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्त्व हिंसा भड़का रहे हैं। जिन्होंने बीते 2-3 दिनों में जमकर हिंसा की है, आईपीएस अधिकारियों पर जानलेवा हमले किए हैं, पेट्रोल पंप पर हिंसा की है, निजी वाहन जला दिए हैं, क्या उनका सरोकार शिक्षा तथा पेपरलीक से हो सकते हैं? क्या यह युवा आंदोलन नेतृत्वहीन है? इन पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। दूसरी ओर आंदोलित सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर सरकार इस मामले में ठोस आश्वासन देती है, तो वह अनशन तोड़ देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पेपर लीक मामलों में अपराधियों को कड़ा दंड देने के लिए नया कानून लाया जाएगा। साथ ही यह भी आश्वासन दिया है कि इस मामले में दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसी के बाद यह अनशन तोड़ा गया है।

डंडे से युवाओं का आक्रोश नहीं दबेगा

प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज से सोशल मीडिया पर आक्रोश की बाढ़ आ गई। सरकार को आखिरकार सीजेपी के कार्यकताओं को बातचीत के लिए बुलाना पड़ा, जिसकी सरकार सत्ता के मद में परवाह ही नहीं कर रही थी। सरकार हालात को समझ ही नहीं पाई और उसने वह सब कुछ किया जो नहीं करना था। सरकार चाहती तो सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाने से पहले उनसे बात कर सकती थी, किसी समझौते पर पहुंच सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सरकार लगभग 100 प्रदर्शनकारियों के एक दल को संसद तक मार्च करने और मंत्रियों व सांसदों के समूह से मिलने के लिए कह सकती थी, लेकिन उन्हें यह जरूरी नहीं लगा। बहरहाल, वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है, जो सरकार के लिए राहत की बात है।

राज्यों और केंद्र में सत्ता में रही कांग्रेस इसलिए सिमटती चली गई क्योंकि उसने देश के लोगों की नब्ज नहीं पहचानी। देश के लोगों की वास्तविक समस्याओं से कांग्रेस अनजान बनी रही। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से देश के आम लोगों की बढ़ती इस दूरी का फायदा उठाया और लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही भाजपा ने देश की समस्याओं के साथ हिंदुत्व और राममंदिर के मुद्दे को देश की समस्याओं के ऊपर चांदी के आवरण में लपेट दिया। हिन्दुत्व और देश की समस्याओं के इस मिश्रण का परिणाम यह रहा कि मतदाताओं ने कांग्रेस और ज्यादातर क्षेत्रीय दलों को सत्ता से हटा कर भाजपा को स्थापित कर दिया। सत्ता में आने के बावजूद भाजपा ने हिन्दुत्व से जुड़े मुद्दों पर असली फोकस बनाए रखा। धीरे-धीरे देश के वास्तविक मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आधारभूत सुविधाएं इत्यादि हाशिए पर जाते रहे। इन मुद्दों को लेकर दर्द से कराहते देश के लोगों की आवाज हिन्दुत्व की आड़ में नक्कारखाने की तूती बन गई। इन मुद्दों को उठाने वालों को देशद्रोही के चश्मे से देखने का सत्ता का नजरिया बन गया। इस पर भी बात नहीं बने तो हिन्दुत्व और राममंदिर की आड़ में मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया। सवाल यही है कि ऐसे भ्रामक मुद्दों की आड़ में आखिर कब तक देश के लोगों के दर्द को दबाए रखा जा सकता है। यह दर्द धीरे धीरे नासूर बनने लगा और असहनीय हो गया। लावा बन कर खदक रही लोगों की पीड़ा के विस्फोट के लिए बस एक जोरदार चिंगारी की जरूरत थी। जब नीट का पेपर आउट हुआ और इस पर देश में जबरदस्त बवाल हुआ, तब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर कैम्पेन चलाया था। इस कैम्पेन में लाखों लोग जुड़ गए थे।

तब भी मोदी सरकार नहीं समझ पाई कि देश के युवाओं का गुस्सा उबाल मार रहा है। सरकार ने इसकी उपेक्षा की। इसके बाद अमरीका में रह रहे दीपके भारत आ गए और जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। अमरीका में रह कर अपनी पढ़ाई कर रहे अभिजीत दीपके ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सोशल मीडिया पर जो मीम्स उन्होंने बनाए हैं, वे दावानल की तरह फैल जाएंगे। बेशक हास्य के प्रतीकात्मक तौर पर ही मीम्स में देश के युवाओं के मुद्दे उठाए गए हों, किन्तु युवाओं को भरोसा होने लगा कि असली मुद्दा यही है। यही वजह रही कि सोशल मीडिया के व्यंग्यात्मक मीम्स ने कुछ दिनों ने प्रसार के सारे रिकार्ड ध्वस्त कर दिए। दीपके के फॉलोवर की संख्या ने कांग्रेस और भाजपा के रिकार्ड को काफी पीछे छोड़ दिया। भाजपा समर्थकों के ऐसे भी कार्टूनों की कमी नहीं थी, जिनमें काकरोच पार्टी के कार्यकताओं को कॉकरोच दिखाते हुए जूतों से ककुचला जा रहा है, उनको जहरीले स्प्रे छिडक कर मारा जा रहा है, उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। तब भी मोदी सरकार यही सोचती रही कि भारत में नेपाल, बांग्लादेश जैसा कुछ नहीं होना वाला। यदि होता भी है तो सरकार को अपनी भारतीय सेना और पुलिस पर पूरा भरोसा था, ऐसे आंदोलनों से निपटने के लिए। यही वजह रही कि दिल्ली प्रशासन ने कॉकरोच पार्टी के कार्यकताओं को प्रदर्शन की अनुमति दे दी। इससे इतना जरूर हुआ कि टकराव टल गया। सरकार भी इनकी ताकत को तोल रही थी। यह प्रदर्शन समाप्त हुआ। सोशल मीडिया पर इसके पक्ष में और खिलाफ कैम्पेन की बाढ़ आ गई थी। केंद्र सरकार ने जंतर मंतर पर सीजेपी के कार्यकताओं के धरने की परवाह नहीं की। किन्तु इस आंदोलन में सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कूद पड़े। सरकार ने फिर भी यही सोचा कि जब इसे जेल में डाल दिया, तभी कुछ नहीं बिगड़ा तो अब यह भी क्या बिगाड़ जाएगा। सोनम वांगचुक 2025 में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह हिंसा हुई थी।

इन प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हुई थी। 90 लोग घायल हुए थे। सरकार ने आरोप लगाया कि वांगचुक ने इस हिंसा को भडकाया। दो दिन बाद 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें फौरन जोधपुर शिफ्ट कर दिया था। 170 दिन से वे जोधपुर जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बाद उन्हें रिहा किया गया। वांगचुक ने जंतर मंतर पर आंदोलन में शामिल होकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। जब वांगचुक का वजन लगातार गिरने लगा तब सरकार को लगा कि ऐसा न हो कि इसे कुछ हो जाए तो हालात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कॉकरोचों को कुचलना तो सरकार के लिए आसान था, किन्तु वांगचुक की भूख हड़ताल के सामने सरकार के सारे हथियार फेल हो गए। पेपर लीक और अन्य मुद्दों के साथ वांगचुक की भूख हड़ताल से तेजी से बिगड़ती तबियत ने धरनार्थी युवाओं में आक्रोश भर दिया। युवाओं ने संसद तक मार्च करके प्रदर्शन किया। पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें कई युवा घायल हो गए। देश के मुख्य मीडिया को दरकिनार कर जिस सोशल मीडिया के जरिए एक तरफा संवाद मोदी सरकार कर रही थी, वही सोशल मीडिया दोतरफा हो गया।

प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज से सोशल मीडिया पर आक्रोश की बाढ़ आ गई। सरकार को आखिरकार सीजेपी के कार्यकताओं को बातचीत के लिए बुलाना पड़ा, जिसकी सरकार सत्ता के मद में परवाह ही नहीं कर रही थी। सरकार हालात को समझ ही नहीं पाई और उसने वह सब कुछ किया जो नहीं करना था। सरकार चाहती तो सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाने से पहले उनसे बात कर सकती थी, किसी समझौते पर पहुंच सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सरकार लगभग 100 प्रदर्शनकारियों के एक दल को संसद तक मार्च करने और मंत्रियों व सांसदों के समूह से मिलने के लिए कह सकती थी, लेकिन उन्हें यह जरूरी नहीं लगा। सरकार संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले सुबह जेपी नड्डा से मिलने के लिए सीजेपी के दो प्रवक्ताओं को बुला सकती थी और संसद में यह बयान दे सकती थी कि मांगों पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों प्रवक्ताओं से मुलाकात तो की, लेकिन यह मुलाकात सुबह संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद हुई। सरकार को भले ही पूरी तरह से समझ में नहीं आया हो, किन्तु काफी हद तक समझ में आ गया है कि देश के नाराज युवाओं को दबाने के लिए फौज और पुलिस का इस्तेमाल घातक साबित हो सकता है, उनकी बात सरकार को सुननी ही पड़ेगी, वरना युवाओं की हुंकार से जैसे बांग्लादेश और नेपाल में सरकार ताश की पत्ते की तरह ढह गई, वही हाल भारत में भी हो सकता है। बहरहाल, वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है, जो राहत की बात है।

योगेंद्र योगी
स्वतंत्र लेखक

सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार और टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च के दौरान छात्रों पर हुई लाठी चार्ज, आंसू गैस और पुलिस का दुर्व्यवहार, आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने के मामले की त्वरित सुनवाई से इंकार कर दिया था। तीन जजों की बेंच के सामने यह याचिका लगाई गई थी। याचिकाकर्ता वकील से मुख्य न्यायाधीश ने कहा, उनकी इस याचिका और आप जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हमें कोई रुचि नहीं है। जब वकील साहब ने दूसरी बार अनुरोध किया तो मुख्य न्यायाधीश ने नाराजी के साथ कहा, हमारा और अपना समय बर्बाद मत करें। मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी की देश भर में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। इससे पहले एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच शब्द का उपयोग किया था। उनका कहना था कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं। उसके बाद इस पर बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और विदेश में कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया। आज वही सीजेपी जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रही। संसद मार्च के दौरान पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया, सैकड़ो छात्र पुलिस लाठी चार्ज में बुरी तरह घायल हुए, प्रदर्शनकारियों के ऊपर पेलट गन एवं इलेक्ट्रिक छड़ी का इस्तेमाल किया गया। सादी वर्दी वाली पुलिस ने कई घंटे तक जबरदस्त मारपीट की। घायलों का इलाज नहीं हुआ। सैकड़ो लोगों को हिरासत में लेकर वहां से ले जाया गया। पुलिस ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की। अधिकांश प्रदर्शनकारियों के पास मोबाइल फोन थे, जो प्रदर्शन स्थल और जंतर मंतर में हर घटना का वीडियो बना रहे थे, कई वीडियो का लाइव प्रसारण हो रहा था, उसमें दिल्ली पुलिस की अमानवीय और अवैधानिक कृत्य इंटरनेट के जरिए सारी दुनिया देख रही थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील भी स्वयं याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस संवेदनशील घटना पर जहां सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना था वहां पर याचिका पेश होने के बाद यह कहना कि हमारा समय बर्बाद ना करें, वीडियो पर हमारी कोई रुचि नहीं है, याचिका की सुनवाई अभी नही होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जिस तरह से सरकार के पक्ष में निर्णय हो रहे हैं अदालतों से सरकार को एक तरह से संरक्षण दिया जा रहा है उसकी प्रतिक्रिया अब पूरे देश में हो रही है। इसके साथ-साथ अब यह चर्चा भी चल पड़ी है जज भगवान नहीं हैं, उन्हें भी नियम कानून और संविधान के तहत काम करना होता है।

नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका का है। न्यायपालिका का अस्तित्व केवल जजों से नहीं होता है। अधिवक्ता और बार काउंसिल भी न्यायपालिका के प्रमुख अंग हैं। यदि न्यायपालिका में जज की कुर्सी पर बैठे न्यायाधीश यदि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में बार काउंसिल और अधिवक्ताओं को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आना होगा। न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष और प्रभावी बनाए रखने की जिम्मेदारी इन तीनों पक्षों की है। अधिवक्ताओं का पंजीकरण बार काउंसिल में होता है जब कोई जज बन जाता है तब उसका पंजीकरण बर काउंसिल से स्थगित कर दिया जाता है। बार काउंसिल अधिवक्ताओं पर अनुशासन, पेशेवर आचरण, न्यायपालिका की सुचिता और अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करता है। जो अधिवक्ता न्यायाधीश बन जाते हैं यदि वह अपने आचरण का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, उनके निर्णय दोषपूर्ण हैं, ऐसी स्थिति में प्रदेश के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शिकायत की जा सकती है। यदि मुख्य न्यायाधीश भी उसकी आंतरिक जांच नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ियां खत्म नहीं हो रही हैं, ऐसी स्थिति में बार काउंसिल और अधिवक्ता जो फैसला जजों द्वारा किए गए हैं और उनमें जो गड़बड़ी हैं उसको लेकर अपील पुनर्विचार और पुनरीक्षण याचिका लेकर जो दोषपूर्ण फैसलें हैं याचिका के माध्यम से उचित न्याय की मांग कर सकते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में बार काउंसिल, अधिवक्ता और जजों की भूमिका स्पष्ट है। तीनों न्यायपालिका की संपूर्ण अवधारणा के परिचायक हैं और तीनों की ही जिम्मेदारी है संविधान और नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना। न्यायपालिका की संवैधानिक जिम्मेदारी है लेकिन जिस तरह से नागरिकों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं और जांच एजेंसियां जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं, सरकार जो कानून बना रही है उसमें संवैधानिक एवं मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जनता के हितों के मामले कई वर्षों से याचिका के माध्यम से लंबित पड़े हुए हैं। वह सब सरकार की मनमानी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद भी उन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है।

अब तो हद हो गई राजधानी दिल्ली में जहां स्वयं सुप्रीम कोर्ट बैठी है वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे जेन-जी युवाओं और युवतियों पर कानून और नियमों का उल्लंघन करते हुए जो जुल्म किया गया, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं से भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। ऐसे में कहा जाने लगा है, कि पिछले कुछ वर्षों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आंशिक फैसला दे रहे हैं। सुनवाई के दौरान तरह-तरह की टिप्पणियां करते हैं, जब फैसले आते हैं तो वह आधे-अधूरे होते हैं। जिस मामले में सरकार को रुचि नहीं होती है उसमें तारीख पर तारीख का खेल अब सभी अदालतों में शुरू हो गया है। नागरिकों के अधिकार पूरी तरह से समाप्त होते चले जा रहे हैं। आम नागरिक प्रताड़ित हो रहा है। राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो चुकी है। एक ही तरह के मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक ही खंडपीठ अलग-अलग फैसला दे रही हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी खंडपीठ के जो फैसले हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो फैसला हो रहे हैं उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अब तो एक नई बात देखने में आने लगी है जो फैसला सरकार को पसंद नहीं आता है उसे पुनर्विचार या पुनरीक्षण याचिका अथवा अध्यादेश लाकर बदल दिया जाता है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। जहां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सरकार भारी पड़ रही है। बहरहाल जंतन मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा उसमें एक सुखद बात यह भी देखने को मिली की सैकड़ो की संख्या में अधिवक्ता प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और न्यायालय में युवाओं के पक्ष को रख रहे हैं। उनके ऊपर उत्पीड़न ना हो इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस स्तर पर अभी यह प्रयास हो रहा है वह बहुत कम है। अधिवक्ताओं को खुलकर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारत में कानून व्यवस्था का राज्य कायम रखना मुश्किल हो सकता है। जब तक नागरिक कानून का पालन करते हैं तभी तक कानून का राज होता है। यदि नागरिक और भीड़ कानून से डरना बंद कर दे तो यह अराजकता की स्थिति होती है। न्यायपालिका के सभी स्तंभों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

(लेखक- सनत जैन)

स्वतंत्र अभिव्यक्ति से लोकतंत्र तक

भारतीय लोकतन्त्र की स्थापना ही राष्ट्र हित में सीमित और मर्यादित स्वतन्त्रता के दायरे में आती है। यह आजादी वर्षों तक मुगल आक्रमणकारियों और अंग्रेज दमनकारियों की यातनाएं सहन करने के बाद हमें मिली है। यह आजादी हमें भीख में नहीं बल्कि लाखों कुर्बानियों के बाद प्राप्त हुई है। इस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों, देश प्रेमियों और स्वतन्त्रता सेनानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अनगिनत संघर्षों, आन्दोलनों और यातनाओं के पश्चात भारत में लोकतन्त्र की स्थापना हुई है।

लोकतन्त्र का अर्थ है- लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए चलाया जाने वाला तंत्र। स्वतन्त्र भारत में संविधान का निर्माण हुआ और जनता को चुनाव का अधिकार प्राप्त हुआ। वोट की चोट से ही लोकतन्त्र मजबूत होता है। संविधान द्वारा प्रदत्त पंचवर्षीय चुनाव प्रणाली ही वास्तव में भारतीय आम नागरिक की ताकत है। जो पांच वर्षों के लिए अपनी मर्जी का नेता तथा सत्ताधारी दल चुन सकता है ताकि उसकी आवाज सुनी जाए। लोकतन्त्र में सत्ताधारी नेता या पार्टी ही नहीं, बल्कि एक जागरूक मतदाता और नागरिक भी महत्वपूर्ण है। देश किस दिशा में जाएगा यह नेता, पार्टियां और सत्ताधारी दल निश्चित नहीं करते बल्कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से वोट से चोट करने वाला मतदाता ही तय करता है।

सरकारों की संरचना भी इसी उद्देश्य के साथ होती है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारें लोगों की सुनें और उनके जनमत के अनुसार कार्य करें अन्यथा लोकतन्त्र की ताकत वोट के माध्यम से सिंहासन उखाड़ फेंकती है। लोकतन्त्र में चार स्तम्भ बहुत महत्वपूर्ण हैं- विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। जहां विधायिका सरकार का मुख्य अंग बनकर कानून बनाने का कार्य करती है, वहीं पर कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। न्यायपालिका देश के कानूनों की रक्षा करती है तथा उनका उल्लंघन होने पर न्याय प्रदान करती है और संविधान की व्याख्या करती है। इसी प्रकार प्रेस अथवा मीडिया को लोकतन्त्र का चौथा और सबसे मजबूत स्तम्भ कहा जाता है, यह लोकतन्त्र तथा संविधान की स्थापना के उद्देश्य से विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका पर पैनी नजर रखती है। सत्ता को पारदर्शी बनाने तथा लोगों में जागरूकता पैदा करना प्रेस के मुख्य कार्यों में आता है। लोकतन्त्र के ये सभी अंग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, इनके व्याखित कार्यों में किसी के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता। वर्तमान में भारतीय लोकतन्त्र के ये चारों ही स्तम्भ समय-समय पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। संविधान द्वारा निर्धारित नियमों और कायदों के अनुसार कार्य न करने पर चारों स्तम्भों पर आरोप-प्रत्यारोप लगते रहते हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगते हैं जिससे लोकतन्त्र पर उंगलियां उठती हैं और संविधान लहूलुहान होता है और उसकी विश्वसनीयता तथा प्रतिष्ठा कम होती है। हालांकि विशेष परिस्थिति में संविधान स्वतः ही अपना रास्ता बना लेता है। भारतीय लोकतन्त्र में विधायिका लोगों के जनादेश के अनुसार कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका में सत्तारूढ़ और विपक्ष का टकराव तथा विरोध एक आम बात है। लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के लिए सत्ताधारी पार्टी के साथ विपक्षी दलों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है लेकिन अनेक बार सत्ताधारी दल द्वारा सत्ता दुरुपयोग और विपक्षी दलों द्वारा सत्ता में वापसी के लिए असंवैधानिक हथियारों का प्रयोग भी लोकतन्त्र को कमजोर करता रहता है। राजनीति चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की, हमेशा साम-दाम-दंड-भेद का सहारा लिया जाता रहा है। इसी खींचतान में अनेक बार नेताओं और राजनीतिक पार्टियों द्वारा लोकतन्त्र की हत्या होती रही है। सत्ताधारी दल संविधान को अपने तरीके से क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। भारतवर्ष में न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है लेकिन न्यायालयों और न्यायाधीशों पर भी पक्षपात तथा भेदभाव के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं।

न्यायपालिका से भी निष्पक्ष और पारदर्शी होने की आशा की जाती है। लोकतन्त्र का चौथा सबसे मजबूत स्तम्भ समझी जाने वाली प्रेस या मीडिया पर भी बिकाऊ होने के आरोप लगते रहते हैं। मीडिया पर प्रभावशाली लोगों व नेताओं की गोदी में बैठने के आरोप लगाना वर्तमान में आम बात हो गई है। व्यंग्यकारों व सत्ता विरोधियों द्वारा आज के मीडिया को ‘गोदी मीडिया’ के नाम से संबोधित किया जाता है। लोकतन्त्र के इन चारों ही स्तम्भों से जनहित में कानून बनाने, उन्हें बिना भेदभाव और पक्षपात तथा न्यायपूर्ण तरीके से लागू करने की आशा की जाती है। वर्तमान में चारों स्तम्भों पर आए दिन आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में संवैधानिक तरीके से प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, नेता, राजनीतिक दल राष्ट्र के लिए जवाबदेह हैं। कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, फिर वह चाहे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही क्यों न हो। ये राष्ट्र सभी एक सौ बयालीस करोड़ भारतवासियों का है और सभी राष्ट्र के प्रति जबावदेह हैं। हम सभी लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संवैधानिक नियमों और कानूनों में बंधे हैं। अति आवश्यक है कि सर्वप्रथम देश के प्रबुद्ध तथा प्रभावशाली लोग संवैधानिक मयार्दाओं का पालन सुनिश्चित करें तथा सत्ता या शक्ति के नशे में चूर कोई भी अमर्यादित कार्य न करें। कोई भी व्यक्ति, नेता या राजनीतिक दल देश के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। लोकतन्त्र में सब अपनी-अपनी सीमाओं में रहें, सबकी बात सुनी जाए, सभी बिना डर के प्रश्न कर सकें, सब विकसित हों, सबकी खुशहाली सुनिश्चित हो, किसी के साथ कोई पक्षपात न हो, सभी सुरक्षित हों तथा निर्भीक होकर अपना जीवनयापन करें, तभी स्वस्थ लोकतन्त्र की स्थापना हो सकती है। लोकतन्त्र को चुस्त दुरुस्त तथा प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेस तथा मीडिया की अहम भूमिका है। वर्तमान में संवैधानिक तरीके से विरोध करने तथा जवाबदेही के लिए प्रश्न पूछने पर देशद्रोही करार दे दिया जाता है। स्वस्थ लोकतन्त्र की दृष्टि से यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ताधारी दलों को भी स्वस्थ लोकतन्त्र की स्थापना के लिए संवेदनशील होना पड़ेगा। ध्यातव्य है कि प्राचीन काल से ही व्यवस्थाओं की दमनकारी नीतियों को जन साधारण द्वारा उखाड़ फैंका गया है। इसीलिए ही लोकतन्त्र में वोट रूपी हथियार प्रत्येक मतदाता के पास शक्ति के रूप में विद्यमान है। सरकार व विपक्ष में संवाद जरूरी है।

प्रो. सुरेश शर्मा, शिक्षाविद

आलेख

परीक्षा व्यवस्था के संकट से लोकतांत्रिक टकराव तक

भारत में शिक्षा और सार्वजनिक भर्ती परीक्षा प्रणाली को लेकर उपजा असंतोष अब एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप ले चुका है। पिछले लगभग एक महीने से हजारों छात्र-छात्राएं और युवा शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि शिक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में गहराते संकट के लिए जवाबदेही तय की जाए तथा परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बहाल की जाए।

पिछले एक दशक में देशभर में केंद्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के 90 से अधिक पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं, जिनसे लगभग 7.5 करोड़ अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। इनमें नीट-यूजी, यूजीसी-नेट, एसएससी तथा विभिन्न राज्यों की पुलिस और शिक्षक भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। भारत की 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 34.5 से 37.1 करोड़ युवा आबादी, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 27 प्रतिशत है, इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। बार-बार परीक्षाओं के निरस्त होने, नियुक्तियों में देरी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली पर उठते सवालों ने लाखों युवाओं के भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया है।हर रद्द हुई परीक्षा और हर प्रश्नपत्र लीक के पीछे वर्षों की मेहनत, परिवारों का आर्थिक निवेश, मानसिक तनाव और टूटते सपने जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि यह आंदोलन केवल परीक्षा सुधार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवाओं के रोजगार, महंगाई और भविष्य की सुरक्षा जैसे व्यापक प्रश्नों से भी जुड़ गया है।शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर तीन सप्ताह से आमरण अनशन कर रहे पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाने के बाद आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जनसमर्थन मिला। इसके बाद छात्रों ने संसद तक मार्च का आह्वान किया।दिल्ली, मुंबई, पटना, बेंगलुरु सहित अनेक शहरों में कैंडल मार्च, धरने और प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। सिख समाज सहित अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बड़ी संख्या में आम नागरिक भी भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री भेजकर आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त कर रहे हैं। इस मानवीय सहयोग ने आंदोलन को सामाजिक संवेदना का भी स्वरूप प्रदान किया है।20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज तथा अन्य बल प्रयोग के माध्यम अपनाए। अनेक प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनके विरुद्ध अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। आंदोलनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ सादे कपड़ों में मौजूद लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसा की तथा बैरिकेडिंग में करंट और कीलों वाली लाठियों का प्रयोग किया गया। पुलिस पर पैलेट गन के इस्तेमाल के भी आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग उठ रही है।

सरकार ने जंतर-मंतर क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए, कई मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद किया तथा पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में बदल दिया। केंद्र सरकार ने जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शनों को संभालने के लिए 3000 अतिरिक्त सशस्त्र पुलिसकर्मी भेजे हैं। यह कदम दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर उठाया गया है।राजधानी के संवेदनशील हिस्सों जंतर-मंतर से संसद भवन तक खासतौर से इसके आसपास के इलाकों को पूरी तरह से छावनी में बदल दिया गया है. यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जमीनी घेराबंदी के अलावा दिल्ली की सुरक्षा को आधुनिक तकनीक से पूरी तरह से लैस किया गया है। इसके बावजूद अगले दिन भी बड़ी संख्या में छात्र आंदोलन स्थल पर पहुंचे और संघर्ष जारी रखने की घोषणा की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित अनेक विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में प्रदर्शन किया और गिरफ्तार हुए। उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह सहित कई नेताओं ने जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया। संसद में भी विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित कई मानवाधिकार संगठनों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग पर चिंता व्यक्त की और लोकतांत्रिक अधिकारों के सम्मान की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से अपनी बात रखने तथा धरना-प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि उनकी लड़ाई केवल किसी एक परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया की नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा एवं भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही स्थापित करने की है। उनकी प्रमुख मांगों में परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक मामलों में त्वरित एवं कठोर कार्रवाई, भर्ती प्रक्रियाओं की समयबद्धता, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में जवाबदेही तय करना तथा शिक्षा व्यवस्था में जनता का विश्वास बहाल करना शामिल है।यह आंदोलन अब केवल परीक्षा सुधार का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि युवाओं के भविष्य, रोजगार और शासन की जवाबदेही से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। यदि सरकार आंदोलनकारी छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी मांगों पर ठोस और समयबद्ध निर्णय लेती है, तो स्थिति शांत हो सकती है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार का रास्ता खुल सकता है। इसके विपरीत यदि केवल पुलिस बल और प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से आंदोलन को दबाने का प्रयास जारी रहता है, तो युवाओं का असंतोष और व्यापक हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह आंदोलन देशव्यापी छात्र-युवा अभियान का रूप लेकर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को भी अपने साथ जोड़ सकता है। इससे संसद, न्यायपालिका और सरकार पर संस्थागत सुधारों का दबाव बढ़ने की संभावना है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी संकट का सबसे प्रभावी समाधान संवाद, पारदर्शिता और जवाबदेही है। इसलिए आने वाले समय में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत, विश्वास बहाली और शिक्षा सुधारों पर ठोस पहल ही यह तय करेगी कि यह संघर्ष टकराव की दिशा में बढ़ता है या फिर भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बनता है।

लेखक- राज कुमार सिन्हा

दिल्ली प्रदर्शन

अब तक क्या क्या हुआ?

- 3 मई- देशभर में नीट यूजी 2026 परीक्षा हुई। 12 मई- पेपर लीक के आरोप लगे, परीक्षा रद्द कर री-एग्जाम की घोषणा की गई।

न्यायपालिका के बयान

- 15 मई- मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं को लेकर कॉकरोच से जुड़ा बयान दिया।

कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन

- 16 मई- अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बनाया, सोशल मीडिया पर आंदोलन शुरू हुआ।
- 6 जून- सीजेपी ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहली बार प्रदर्शन किया।
- 20 जून- कॉकरोच पार्टी ने जंतर-मंतर पर दूसरा विरोध प्रदर्शन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ के मांग।
- 28 जून- कॉकरोच पार्टी का समर्थन कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए।
- 20 जुलाई- संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सीजेपी ने 'चलो संसद' मार्च निकाला। प्रदर्शन में शामिल लोगों पर लाठीचार्ज।
- 21 जुलाई- राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया।
- 21 जुलाई- संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने नीट, लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा उठाया।
- 22 जुलाई- संसद में लगातार तीन दिन विपक्ष ने प्रदर्शन जारी रखा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
- 23 जुलाई- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया। लेकिन विपक्ष ने इस्तीफे की मांग रखी।
- 24 जुलाई- पेपर लीक के बीच एनटीए ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। इनके खिलाफ केस भी दर्ज होगा।
- 25 जुलाई- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया।

राहुल गांधी के साथ दिखीं छात्र नेताओं की तिकड़ी, आंदोलन में निभाई अहम भूमिका

नई दिल्ली, 25 जुलाई (वेब वार्ता)। जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में तीन छात्र नेता विशेष रूप से चर्चा का केंद्र रहीं। नेहा बोरा, अंजलि और दानिश अली आंदोलन की प्रमुख आवाजों के रूप में सामने आई हैं। राहुल गांधी ने इनके साथ मंच साझा करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई तथा छात्रों के साथ हुई कथित हिंसा पर कार्रवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्षमा मांगने की भी मांग की।

जानकारी के अनुसार, तीनों छात्र नेता ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़ी हुई हैं। नेहा बोरा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि अंजलि दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई की अध्यक्ष हैं। दानिश अली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ की संयुक्त सचिव होने के साथ विश्वविद्यालय में शोधार्थी भी हैं।

नेहा बोरा बनीं आंदोलन का प्रमुख चेहरा

जंतर-मंतर पर आंदोलन की शुरूआत से ही नेहा बोरा लगातार सक्रिय रहीं। अपनी प्रभावशाली वक्तृत्व शैली के कारण वह आंदोलन की प्रमुख आवाज के रूप में उभरीं। नेहा बोरा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कला एवं सौंदर्य अध्ययन केंद्र में शोध कर रही हैं। 28 जून को सोनम वांगचुक द्वारा अनशन शुरू किए जाने के बाद उन्होंने भी अनशन में भाग लिया और लगभग 23 दिनों तक आंदोलन का हिस्सा रहीं।

अंजलि ने संभाली दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की अगुवाई

दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा अंजलि भी आंदोलन के दौरान लगातार सक्रिय रहीं। वह छात्र संगठन की दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई का नेतृत्व करती हैं। वर्ष 2025 में हुए छात्रसंघ चुनाव में उन्होंने उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ा था। आंदोलन के दौरान उन्होंने छात्रों के बीच समन्वय की भूमिका निभाई। 20 जुलाई को आयोजित संसद चलो मार्च के दौरान वह घायल भी हुई थीं।

दानिश अली ने निभाई नेतृत्वकारी भूमिका

दानिश अली भी आंदोलन के नेतृत्वकारी चेहरों में शामिल रहीं। वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ की संयुक्त सचिव हैं और विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में शोधार्थी हैं। छात्र राजनीति के साथ-साथ वह मध्य प्रदेश की राज्य स्तरीय थ्रो बॉल और क्रिकेट खिलाड़ी भी रह चुकी हैं।

छात्र आंदोलन में बढ़ी विभिन्न संगठनों की भागीदारी

जंतर-मंतर पर प्रारंभ हुआ आंदोलन समय के साथ व्यापक स्वरूप लेता गया। इसमें विभिन्न छात्र संगठनों और विपक्षी दलों का समर्थन भी देखने को मिला। राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में इन छात्र नेताओं की मौजूदगी को आंदोलन में छात्र नेतृत्व की सक्रिय भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। आंदोलन से जुड़े पक्षों का कहना है कि शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर उनकी आवाज आगे भी बुलंद रहेगी।

कैमरे से ढाई हजार संदिग्ध पहचाने, अबतक 15 एफआईआर

नई दिल्ली, वेब वार्ता। सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर और टॉलस्टॉय मार्ग पर लगाए गए अत्याधुनिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) कैमरों की मदद से करीब ढाई हजार संदिग्धों की पहचान की गई है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 15 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। तकनीकी विंग ने तीन दिनों के एफआरएस कैमरों के फुटेज को जब अपने क्रिमिनल डेटाबेस से सिंक किया तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। भीड़ में सैकड़ों संदिग्ध चिह्नित किए गए हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होने का शक है। नई दिल्ली जिले के विभिन्न थानों (संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, मंदिर मार्ग आदि) में संगीन धाराओं के तहत अब तक 15 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें हत्या का प्रयास, दंगा भड़काना, डकैती और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने जैसी गैर-जमानती धाराएं शामिल हैं।

राष्ट्रहित में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, रेखा गुप्ता ने जताया आभार

नई दिल्ली, 25 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके सार्वजनिक जीवन और शिक्षा क्षेत्र में दिए गए योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया यह निर्णय नैतिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रेखा गुप्ता ने अपने वक्तव्य में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में समर्पण और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को गति मिली और शिक्षा व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा मिला, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ तथा विद्यार्थियों के लिए नए अवसर उपलब्ध हुए। उन्होंने उनके योगदान को देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। रेखा गुप्ता ने धर्मेंद्र प्रधान के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा।

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहली सफलता, सीजेपी की 3 मांगें अब भी बाकी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे अपने आंदोलन की पहली बड़ी सफलता बताया है।

नई दिल्ली, वेब वार्ता

हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि उसकी तीन प्रमुख मांगें अभी भी लंबित हैं और उनके पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 20 जून से जंतर-मंतर पर छात्र हितों और नीट परीक्षा विवाद से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन स्थल पर समर्थकों ने खुशी व्यक्त की, लेकिन संगठन ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। संगठन ने सामाजिक माध्यम के जरिए अपनी तीन प्रमुख लंबित मांगों की जानकारी दी। पहली मांग उन छात्र-छात्राओं के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की है, जिनकी कथित रूप से परीक्षा विवाद के दौरान आत्महत्या से मृत्यु हुई। दूसरी मांग प्रदर्शन में शामिल छात्रों के विरुद्ध दर्ज मामलों और कानूनी कार्रवाई को समाप्त करने की है।

तीसरी मांग 20 जुलाई को आयोजित ₹संसद चलो₹ मार्च के दौरान छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने की है। संगठन का आरोप है कि उस दौरान हुए बल प्रयोग में अनेक छात्र घायल हुए थे। इसके साथ ही हिरासत में लिए गए छात्रों के विरुद्ध आगे कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने की भी मांग दोहराई गई है।

उधर, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने त्यागपत्र में कहा कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं था और उन्होंने प्रारंभ से ही अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने यह भी कहा कि देश में बनी परिस्थितियों का कोई राष्ट्रविरोधी तत्व लाभ न उठा सके, राष्ट्रीय एकता बनी रहे तथा विद्यार्थियों का भविष्य कानूनी उलझनों में न फंसे, इसी उद्देश्य से उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र सौंपा है। जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में चल दूरभाष आधारित अंतरजाल सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार भी बंद किए गए थे, जिन्हें बाद में चरणबद्ध तरीके से खोल दिया गया।

जंतर-मंतर पर पथराव, फोर्स ने संभाला हालात; मेट्रो के 3 स्टेशनों के गेट खुले

नई दिल्ली, 25 जुलाई (वेब वार्ता)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के बाद जंतर-मंतर पर शनिवार को पथराव की घटना हो गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का लाठीचार्ज किया। सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के एक समूह के कथित तौर पर हिंसक होने और सुरक्षाकर्मियों पर पथराव करने के बाद यह झड़प शुरू हुई। फिलहाल हालात काबू में हैं। इलाके में पर्याप्त फोर्स तैनात है। सूत्रों के मुताबिक, शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के कुछ ही देर बाद जंतर-मंतर पर हालात बिगड़ गए। जंतर-मंतर पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।

प्रथम पृष्ठ के शेष...

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे...

उन्होंने कहा कि इन मांगों के पूरा होने तक संगठन संघर्ष जारी रखेगा। अभिजीत दीपके ने महात्मा गांधी के शांतिपूर्ण आंदोलन के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि संगठन ने अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें रखने का मार्ग अपनाया। उन्होंने समर्थकों से संयम बनाए रखने और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन जारी रखने की अपील की। उधर, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने त्यागपत्र में कहा कि राष्ट्रसेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि वह शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में विद्यार्थियों का भविष्य किसी प्रकार की कानूनी अथवा अन्य कठिनाइयों में न उलझे, इसी भावना से उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंपा।

उल्लेखनीय है कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा नीट परीक्षा विवाद को लेकर जंतर-मंतर पर कई दिनों से आंदोलन चलाया जा रहा था। इस आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 28 जून से अनशन आरंभ किया था, जिसे बाद में सरकार से वार्ता और स्वास्थ्य कारणों के चलते समाप्त किया गया।

धर्मेंद्र प्रधान ने दिया...

उन्होंने आगे कहा, किंतु 3 मई 2026 को हुई NEET-UG की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए।

इसके लिए whole of government approach के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही, छात्रों, अभिभावक और माता-पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से, इसपर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूँ। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं हैं, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निमार्ता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं।

भारत की युवाशक्ति ही इस देश की असली ताकत

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पोस्ट में आगे कहा है, पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुःखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवाशक्ति ही, इस देश की असली ताकत है। देश की युवाशक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है।

निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं

प्रधान ने आगे कहा, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही, मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रसेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्रीजगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा।

सरकार से सहमति के बाद सीजेपी ने आंदोलन समाप्त किया

नई दिल्ली, 25 जुलाई (वेब वार्ता)। जंतर-मंतर पर कई दिनों से चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शनिवार को सरकार के साथ तीसरे दौर की वार्ता के बाद समाप्त हो गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ बैठक कर विभिन्न मांगों पर चर्चा की। वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की।

बैठक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि सरकार के साथ तीन चरणों में विस्तृत बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आंदोलन की तीन प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के विरुद्ध दर्ज मामलों तथा प्राथमिकी को वापस लेना और भविष्य में आंदोलन से जुड़े छात्रों एवं आयोजकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आश्वासन शामिल था।

आशुतोष रांका ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ आंदोलन की पहली मांग पूरी हो चुकी है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सोनम वांगचुक ने बताया लोकतंत्र की जीत

नई दिल्ली, 25 जुलाई (वेब वार्ता)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि यह शांतिपूर्ण जनआंदोलन, धैर्य और दृढ़ता की सफलता का प्रतीक है।

सोनम वांगचुक ने सामाजिक माध्यम पर जारी अपने संदेश में लिखा कि यह सीधा लोकतंत्र है, जो सड़कों से निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि यह शांति, धैर्य और अटूट संकल्प की जीत है।

उन्होंने सीजेपी और देश के युवाओं को बधाई देते हुए उन सभी नागरिकों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने भय से ऊपर उठकर देश के विभिन्न हिस्सों से अपनी आवाज बुलंद की। उनके अनुसार अब जवाबदेही सुनिश्चित करने के बाद सुधार की दिशा में आगे बढ़ने का समय है।

उल्लेखनीय है कि सोनम वांगचुक ने हाल ही में जंतर-मंतर पर 20 दिनों तक अनशन किया था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनकी यह प्रतिक्रिया राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

जंतर-मंतर प्रदर्शन पर फर्जी खबरों का जाल, 400 से अधिक हैंडल चिन्हित: दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली, 25 जुलाई (वेब वार्ता)। जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं और फर्जी सामग्री के प्रसार को लेकर दिल्ली पुलिस ने शनिवार को विशेष प्रेस वार्ता आयोजित कर सोशल माध्यम पर फैलाए जा रहे दावों का खंडन किया। पुलिस ने बताया कि अब तक 400 से अधिक ऐसे सामाजिक माध्यम खातों की पहचान की गई है, जिनके माध्यम से भ्रामक और मनगढ़ंत सामग्री प्रसारित की जा रही थी। इन खातों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मध्य जिला के पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि जांच के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे संदेश, वीडियो और परिवर्तित दृश्य सामग्री सामने आई, जिनका उद्देश्य लोगों को गुमराह करना था। उन्होंने कहा कि कई वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक बयानों में छेड़छाड़ कर उन्हें भ्रामक रूप में प्रसारित किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं

हुई थी। सामाजिक माध्यम पर एक युवती की मृत्यु का जो दावा किया गया, वह पूरी तरह असत्य पाया गया। इसी प्रकार सेना की तैनाती से संबंधित खबरों को भी पुलिस ने निराधार बताया।

प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने यह भी कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से संबंधित एक फर्जी वीडियो भी प्रसारित किया गया, जिसका वास्तविक घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है। पुलिस के अनुसार, ऐसे वीडियो और संदेशों के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ फर्जी सामाजिक माध्यम खाते पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे थे, जिनके माध्यम से भ्रामक सामग्री प्रसारित की जा रही थी। पुलिस इन खातों की गतिविधियों की विस्तृत जांच कर रही है और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी समाचार, वीडियो अथवा संदेश पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि अवश्य करें। पुलिस ने कहा कि अपुष्ट और भ्रामक सामग्री साझा करने से बचें तथा केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें।

दिल्ली के वसंत कुंज में कार फिसलकर खुले नाले में गिरी, युवक की मौत

नई दिल्ली, 25 जुलाई (वेब वार्ता)। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक मोड़ पर नियंत्रण खोने के बाद 20 साल के एक युवक की कार एक खुले नाले में जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। यह दुखद घटना शुक्रवार सुबह हुई, जब यशवेंद्र और उसकी दोस्त नांगल देवत इलाके से घर लौट रहे थे। नांगल देवत रेड लाइट के पास एक तीखे मोड़ पर सड़क के फिसलन भरे होने के कारण यशवेंद्र का कार से नियंत्रण छूट गया। इसके बाद कार एक नाले में गिरकर पलट गई।

जेन-जी ने बताया 'विश्वगुरु' का अर्थ : गीतांजलि आंगमो

नई दिल्ली, 25 जुलाई (वेब वार्ता)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने देश के युवाओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारत के ₹विश्वगुरु₹ होने का वास्तविक अर्थ नई पीढ़ी ने अपने आचरण से स्पष्ट किया है। उन्होंने आंदोलन में शामिल युवाओं की शांतिपूर्ण और अहिंसक भागीदारी को लोकतांत्रिक मूल्यों का उदाहरण बताया।

सामाजिक माध्यम पर जारी अपने संदेश में गीतांजलि आंगमो ने कहा कि भारत की नई पीढ़ी ने बिना किसी बड़े उपदेश के सनातन धर्म के मूल्यों को अपने व्यवहार में उतारा है। उनके अनुसार, युवाओं ने बिना घृणा के साहस, बिना हिंसा के दृढ़ता और बिना अंधभक्ति के राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया है। उन्होंने लिखा कि दुनिया के अनेक देशों के समवयस्क युवाओं की तुलना में भारतीय युवाओं ने यह दिखाया है कि अपने ही देश को नुकसान पहुंचाए बिना भी अन्याय के विरुद्ध मजबूती से खड़ा हुआ जा सकता है। उनके

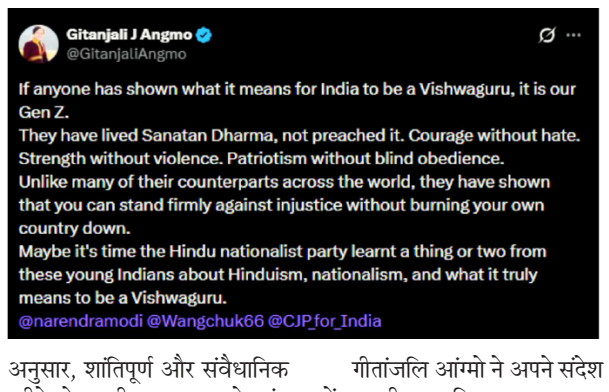

अनुसार, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखना लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है।

गीतांजलि आंगमो ने अपने संदेश में यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि सत्तारूढ़ दल इन युवाओं से हिंदू धर्म, राष्ट्रवाद और विश्वगुरु होने के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करे। उन्होंने संकेत दिया कि युवाओं के व्यवहार और लोकतांत्रिक मूल्यों से समाज तथा राजनीति दोनों को सीख लेने की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि जंतर-मंतर पर पिछले 36 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा था। आंदोलन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी समर्थन में अनशन पर बैठे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन से जुड़े कई पक्षों ने इसे अपनी पहली बड़ी सफलता बताया है, जबकि आंदोलनकारी अभी भी अपनी अन्य मांगों के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक चले अपने अनशन को शुक्रवार देर रात समाप्त किया था। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और आंदोलन से जुड़े घटनाक्रम पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

संक्षिप्त वार्ता

अंकित विशाल ने आधुनिक मत्स्य पालन से लिखी सफलता की नई कहानी

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। सरकारी नौकरी की तलाश में वर्षों तक प्रयास करने के बाद जब सफलता नहीं मिली, तब सण्डीला तहसील के युवा अंकित विशाल ने हार मानने के बजाय मत्स्य पालन को अपना भविष्य बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं, तकनीकी प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता का लाभ लेकर उन्होंने आधुनिक मत्स्य पालन के क्षेत्र में ऐसी सफलता हासिल की, जो आज जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है।

सहायक निदेशक मत्स्य डॉ. मुनीश कुमार ने बताया कि अंकित विशाल ने मत्स्य विभाग से संपर्क कर प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने आईसीएआर-सीआईएफए, केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (सीआईएफई) तथा सीआईएफआरआई सहित प्रतिष्ठित संस्थानों से आधुनिक मत्स्य पालन का प्रशिक्षण लिया।

बार एसोसिएशन ने गंभीर मुकदमों में वांछित अधिवक्ताओं का विवरण मांगा

वेब वार्ता, फरुखाबाद

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निदेशों के अनुपालन में बार एसोसिएशन फतेहगढ़ (जनपद फरुर्खाबाद) ने गंभीर आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे अधिवक्ताओं से उनके मामलों का विवरण मांगा है। इस संबंध में बार एसोसिएशन के महासचिव कुंवर सिंह यादव, एडवोकेट ने सभी अधिवक्ता साथियों के लिए शनिवार को सूचना जारी की है।

उन्होंने बताया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से एक पत्र मिला है। 23 जुलाई 2026 के पत्रांक 711/26 के अनुपालन में जिन अधिवक्ताओं के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें अपने सभी संबंधित मुकदमों का पूरा विवरण 10 दिनों के भीतर बार एसोसिएशन फतेहगढ़ कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि प्राप्त विवरण को संकलित कर निर्धारित समय सीमा के भीतर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजा जाएगा। अधिवक्ताओं से समय पर जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की गई है, ताकि परिषद के निदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इस निर्देश को बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ताओं के अभिलेखों के सत्यापन और आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।

झपकी आने से आगे चल रहे अज्ञात वाहन से टकराया पिकअप, चालक गंभीर

औरैया, (वेब वार्ता)

उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में सदर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कानपुर-इटावा मार्ग पर औरैया-कानपुर देहात सीमा के पास शनिवार तड़के सब्जी से लदी पिकअप आगे चल रहे अज्ञात भारी वाहन से पीछे टकरा गई। दुर्घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाने के साथ क्षतिग्रस्त वाहन हटवाकर यातायात सामान्य कराया।

सदर कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र में मामा-भांजा ढाबा के सामने करीब 1:50 बजे पिकअप संख्या यूपी-83 सीटी-5941 कानपुर से इटावा की ओर सब्जी लेकर जा रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि चालक गजेंद्र पाल (27) निवासी नगला हीरा, थाना नगला खंगर, जनपद फिरोजाबाद को वाहन चलाते समय झपकी आ गई। इससे पिकअप आगे चल रहे अज्ञात भारी वाहन से पीछे जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को एंबुलेंस से पहले 50 शैय्या जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने 100 शैय्या अस्पताल चिचौली रेफर कर दिया। हादसे की सूचना चालक के परिजनों को भी दे दी गई है। अज्ञात वाहन की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

कूड़ा डालने के विवाद में दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, आठ घायल

औरैया, वेब वार्ता

उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में फफूंद थाना क्षेत्र के बनके पूर्वा गांव में शनिवार सुबह कूड़ा (घूरा) डालने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे। मारपीट में दोनों पक्षों के कुल आठ लोग घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही फफूंद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) दिबियापुर पहुंचाया। वहां चिकित्सक डॉ. अब्दुल करीम ने प्राथमिक उपचार किया। गंभीर रूप से घायल सुनीता देवी और रवि की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए 100 शैय्या अस्पताल, चिचौली रेफर कर दिया गया। प्रथम पक्ष के घायल बबलू ने आरोप लगाया कि पड़ोसियों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया, जिससे सुनीता देवी, नितिन और रवि घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के लायक सिंह का कहना है कि उन पर दूसरे पक्ष ने हमला किया, जिसमें वह स्वयं, नवाब सिंह और शिवा सहित अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच कूड़ा डालने को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा था। सभी घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों से तहरीर मिलने के बाद साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

53 करोड़ के संदिग्ध ट्रांजेक्शन से खुला राज

250 करोड़ के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का 25 हजारी इनामी गिरफ्तार

कानपुर। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले 250 करोड़ रुपये के साइबर ठगी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने फर्जी बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम को ठिकाने लगाने वाले 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

वेब वार्ता, हरी शंकर शर्मा

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि साइबर क्राइम थाना पुलिस (कानपुर) ने स्क्रैप कारोबारी के 3 बैंक खातों में 53 करोड़ का संदिग्ध लेनदेन मिला। पुलिस ने बताया कि ठगी की रकम को कई खातों में घुमाकर कैलिफोर्निया (अमेरिका) भेजने के साक्ष्य मिले।

फर्जी दस्तावेजों से खुलवाए खाते, विदेश भेजी गई रकम

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते खुलवाने और उन्हें साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराने का काम करता था। हाल ही में एक स्क्रैप कारोबारी के नाम संचालित तीन बैंक खातों की जांच के दौरान पुलिस को लगभग 53 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता चला, जो इस पूरी कार्रवाई का मुख्य आधार बना। ठगी की रकम के वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए अपराधी पैसे को पहले देश के कई खातों में लेयरिंग (घुमाना) करते थे और फिर इसे विदेश ट्रांसफर कर देते थे। प्रारंभिक जांच में एजेंसियों को इस रकम के कैलिफोर्निया तक पहुंचने के पुख्ता सबूत मिले हैं।

250 करोड़ के फ्रॉड नेटवर्क पर शिकंजा, बैंकिंग मिलीभगत की भी जांच

अब तक की तफ्तीश में इस गिरोह द्वारा करीब 250 करोड़ रुपये के अवैध लेन-देन की बात सामने आ चुकी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह से जुड़े कई बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से फ्रीज करा दिया है। पुलिस आधिकारियो ने बताया कि मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।

बड़े चेहरे होंगे बेनकाब

जांच एजेंसियां इस पहलू पर भी काम कर रही हैं कि क्या इस नेटवर्क को चलाने में बैंकिंग सिस्टम से जुड़े किसी व्यक्ति या कर्मचारी की मिलीभगत थी। जांच पूरी होने पर इस सिंडिकेट से जुड़े कई और बड़े चेहरों का पदार्फाश होने की संभावना है।

रविदास का समरसता मंत्र बनेगा 2027 का महामंत्र

लखनऊ, वेब वार्ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सबसे बड़े सामाजिक-राजनीतिक अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है। पार्टी अब गुरु रविदास के समरसता, समानता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को केंद्र में रखकर अनुसूचित जाति की 66 उपजातियों तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। संगठन की कोशिश इस अभियान के जरिए दलित समाज के विभिन्न वर्गों को सामाजिक समरसता, सामाजिक एकजुटता और व्यापक हिंदू समाज के साझा विमर्श से जोड़ने की है।

राजनीतिक हलकों में इसे 2027 के चुनाव से पहले भाजपा की सबसे बड़ी सामाजिक इंजीनियरिंग के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी का मानना है कि 4.13 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति मतदाताओं के बीच स्थाई सामाजिक संवाद ही 2027 की चुनावी रणनीति की मजबूत नींव बन सकता है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कहा कि अभियान गुरु रविदास जयंती से शुरू होकर उनके 650वें प्रकाश पर्व तक चरणबद्ध तरीके से चलेगा। प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ स्तर तक सम्मेलन, संगोष्ठियां, सामाजिक संवाद, मंदिर संपर्क, घर-घर संपर्क और प्रबुद्ध वर्ग की बैठकें आयोजित होंगी। हमारा उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन करना नहीं, बल्कि संत रविदास के समरसता संदेश को सामाजिक अभियान का रूप देना है।

बसपा के सामाजिक आधार पर नजर

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी 4.13 करोड़ से अधिक है। इनमें चमार-जाटव, पासी, कोरी, धोबी, वाल्मीकि, खटीक, धनुक, मुसहर, दुसाध समेत 66 उपजातियां शामिल हैं। दशकों तक इन वर्गों का बड़ा हिस्सा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राजनीति की रीढ़ माना जाता रहा है। अब भाजपा की रणनीति इन सभी उपजातियों तक अलग-अलग सामाजिक संपर्क स्थापित कर अपना आधार और मजबूत करने का है। संगठन ने प्रत्येक जिले में रविदास मंदिरों, दलित छात्रावासों, कोचिंग संस्थानों, समाज के शिक्षकों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं, उद्यमियों, सामाजिक कार्यकताओं और प्रभावशाली परिवारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन लोगों के माध्यम से गांव, वार्ड और बूथ स्तर तक संपर्क अभियान चलाया जाएगा।

रामनगर क्षेत्र में प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने किया निरीक्षण

वाराणसी, वेब वार्ता। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रभारी जनपद वाराणसी के रामनगर क्षेत्र में शनिवार की सुबह सेवा बस्तियों एवं अन्य क्षेत्रों का भ्रमण कर मूलभूत नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण किया।

प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि रामनगर में बारिश के कारण कई जगह जलभराव और कीचड़ हुआ है। जिसके निस्तारण के लिए नगर निगम के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करते हुए स्वच्छता कार्य कराना आवश्यक है। उन्होंने कूड़ा निस्तारण समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर आयुक्त को विशेष रूप से रामनगर क्षेत्र का ध्यान देने के लिए निर्देशित किया।

एआईएनएससी-2026 से लौटे एनसीसी कैडेटों का एडीजी ने किया अभिनंदन, 11 पदक विजेताओं को किया सम्मानित

वाराणसी, वेब वार्ता

अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी), यूपी निदेशालय एनसीसी मेजर जनरल गौरव गौतम, विशिष्ट सेवा मेडल ने शनिवार को ग्रुप मुख्यालय 'ए', वाराणसी के तत्वावधान में 7 यूपी नेवल यूनिट एनसीसी का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने 30 जून से 12 जुलाई 2026 तक महाराष्ट्र के लोनावला स्थित आईएनएस शिवाजी में आयोजित ऑल इंडिया नौ सैनिक कैंप 2026 में प्रतिभाग कर लौटे कैडेटों से मुलाकात कर उनका अभिनंदन किया।

एडीजी ने कैडेटों से शिविर के दौरान प्राप्त अनुभवों, प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं और उनके प्रदर्शन की जानकारी ली। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के इस प्रतिष्ठित शिविर में कैडेटों के अनुशासन, समर्पण, नेतृत्व क्षमता और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर युवाओं के व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व क्षमता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि एआईएनएससी जैसे राष्ट्रीय मंच पर प्रतिभाग करना प्रत्येक कैडेट के लिए गौरव की बात है।

इस अवसर पर मेजर जनरल गौरव गौतम ने एआईएनएससी-2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कुल 11 पदक जीतने वाले कैडेटों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इन कैडेटों की उपलब्धियां पूरे यूपी निदेशालय के लिए गर्व का विषय हैं और अन्य कैडेटों के लिए प्रेरणास्रोत भी हैं। एडीजी ने अधिकारियों, एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों (एएनओ), पीआई स्टाफ और प्रशिक्षकों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके समर्पित प्रयासों, उत्कृष्ट प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के कारण यूपी निदेशालय के कैडेट लगातार राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी प्रदेश के कैडेट राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे।

स्वर्ण पदक विजेता

- कैडेट अमित कुमार
- लीडिंग कैडेट पुष्कर शर्मा
- कैडेट आकाश कुमार
- कैडेट आयुषी मौर्य
- कैडेट आस्था श्रीवास्तव

कांस्य पदक विजेता

- कैडेट स्वर्णिमा साहू
- लीडिंग कैडेट नेहा कुमारी
- लीडिंग कैडेट अंकुर यादव
- कैडेट स्वास्तिक दुबे
- कैडेट रिया दुबे
- कैडेट वंश शर्मा

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद सपा में जश्न, रामज्ञान गुप्ता बोले- झुक गई मोदी सरकार, लोकतंत्र की हुई जीत

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद हरदोई में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकताओं ने खुशी का इजहार किया। सपा के वरिष्ठ नेता रामज्ञान गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकताओं ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया और इसे छात्रों एवं युवाओं के संघर्ष की जीत बताया।

इस मौके पर रामज्ञान गुप्ता ने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि जनता और युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा है। यह अहंकार की हार और लोकतंत्र की जीत है।

उन्होंने कहा कि युवाओं के आंदोलन की यह दूसरी बड़ी जीत है। पहली जीत उस समय मिली थी, जब देश के युवा डर और दबाव से बाहर निकलकर अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आए। अब सरकार को उनकी मांगों के आगे

झुकना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अभी भी कई महत्वपूर्ण फैसले होने बाकी हैं। जब तक युवाओं के भविष्य से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान नहीं होगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। तभी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा।

रामज्ञान गुप्ता ने कहा, ₹कहा जाता था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन आज हालात सबके सामने हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।

उन्होंने छात्रों और युवाओं को इस जीत की बधाई देते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी ताकत होती है और जब युवा एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं तो सरकारों को भी निर्णय बदलने पड़ते हैं।

इस अवसर पर सपा नेताओं एवं कार्यकताओं ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई और एक-दूसरे को बधाई दी। कार्यक्रम में सुधीर गुप्ता मिन्ना, जुगल गुप्ता, अवनीश यादव, धर्मेंद्र यादव 'दीपू', श्याम गुप्ता, विपिन गुप्ता, शुभम गुप्ता, सोनू गुप्ता, रुस्तम श्रीवास्तव, राजीव गुड्डू, लोकेश, पिंटू, अंकित वर्मा, रामजी वर्मा, शिवम यादव, गौरव यादव, दुर्गेश, रामदत्त गुप्ता, चंद्रप्रकाश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

चौपाल सागर के पास मोबाइल लूट का खुलासा, तीन आरोपी दबोचे

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। कोतवाली देहात पुलिस ने चौपाल सागर के पास हुई मोबाइल लूट की घटना का 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, बावन चुंगी निवासी सौरभ पुत्र राम सिंह ने 24 जुलाई को कोतवाली देहात में तहरीर देकर बताया था कि 22 जुलाई को वह

ई-रिक्शा से जा रहे थे। इसी दौरान चौपाल सागर के निकट बाइक सवार तीन युवकों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। विवेचना के दौरान मामले में अन्य धाराएं भी बढ़ाई गईं। जांच के दौरान पुलिस ने ग्राम अटवा असिगांव निवासी राजा पुत्र स्व. रावेंद्र सिंह, आकाश पुत्र धर्मपाल तथा करुणा शंकर पुत्र राजाराम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर लूटा गया मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मामले में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक पवन प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक पंकज कुमार सहित कोतवाली देहात पुलिस टीम की प्रमुख भूमिका रही।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्लान को मंजूरी

वाराणसी, वेब वार्ता। सावन मास में श्री काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। इस बार श्रद्धालु मणिकर्णिका गली और गंगा द्वार के रास्ते सीधे मंदिर के गेट नंबर-4 तक पहुंच सकेंगे। इससे दर्शनार्थियों को आने-जाने में आसानी होगी और मंदिर परिसर में भीड़ का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को गंगा द्वार से गेट नंबर 4 तक बिना रोक-टोक आने-जाने के लिए बाईपास मार्ग की सुविधा मिलेगी। इस रास्ते की मदद से श्रद्धालुओ मणिकर्णिका गली से भी मंदिर कॉरिडोर के अहिल्याबाई चौक तक पहुंच सकेंगे। भारत माता मंदिर के पास बने फूड प्लाजा में नाश्ता करने के बाद वे सीधे शंकराचार्य चौक होते हुए मंदिर परिसर से बाहर निकल सकेंगे। इस मार्ग पर मोबाइल लेकर आना-जाना भी प्रतिबंधित नहीं रहेगा। अब तक दर्शन कर बाहर निकलने वाले श्रद्धालुओं को गंगा द्वार जाने से तो नहीं रोका जाता था, लेकिन वापस शंकराचार्य चौक की जाने के लिए उन्हें लाइन में लगना पड़ता था या मणिकर्णिका गली की ओर से बाहर निकलना पड़ता था। हालांकि, इस बाईपास मार्ग का उपयोग करने वाले श्रद्धालुओं को मुख्य मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।

हरदोई के सुरसा में युवक की बांके से काटकर हत्या, एक आरोपी हिरासत में

चार साल पुरानी रंजिश में वारदात, परिजनों की तहरीर पर दो के खिलाफ हत्या का मुकदमा

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। सुरसा थाना क्षेत्र के जीतपुरवा गांव में शुक्रवार रात चार साल पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। गांव के बाहर बाजार में कहासुनी के बाद दो लोगों ने युवक पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर दो नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, ग्राम जीतपुरवा मजरा खजराहा निवासी सोहित कुमार (पुत्र कोमिल) शुक्रवार रात करीब आठ बजे गांव के बाहर स्थित बाजार में था। इसी दौरान गांव के ही अमर सिंह पुत्र रामरूप और जितेंद्र पुत्र परशुराम से किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। आरोप है कि

दोनों ने धारदार हथियार (बांका) से सोहित के सिर पर कई वार कर दिए, जिससे वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा।

घटना की सूचना डायल-112 पर मिलने के बाद सुरसा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल हरदोई मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में तनाव का माहौल बन गया।मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने आरोपी जितेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।क्षेत्राधिकारी नगर अजीत चौहान ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा मामले में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।

तेज रफ्तार कार की टक्कर से तीन बाइक सवार घायल, एक की हालत गंभीर

वेबवार्ता/हरदोई। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के कोथावा चौकी अंतर्गत प्रतापनगर-संडीला मार्ग पर नगवा मोड़ के पास शनिवार को तेज रफ्तार कार की टक्कर से तीन बाइक सवार घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोथावा पहुंचाया, जहां एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार, अटिया मझिगवा गांव निवासी उमेश (19) पुत्र मुकेश, छुन्नी (20) पुत्र शौकीन और जिगिंदर (22) पुत्र लक्ष्मी बर्तनों की फेरी कर अपनी-अपनी बाइकों से घर लौट रहे

थे। इसी दौरान नगवा मोड़ के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार (संख्या यूपी-77-एयू-2080) ने तीनों बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं और तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस व 108 एंबुलेंस को सूचना दी। कोथावा चौकी प्रभारी विजयंत मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोथावा भिजवाया।

तेहरान से यमन पहुंची रहस्यमय उड़ान पर मचा हड़कंप

तेहरान। तेहरान से यमन पहुंची एक रहस्यमय उड़ान अब अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव का केंद्र बन गई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 13 जुलाई को ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के जनाजे से लौट रहे इस विमान में आम यात्रियों के अलावा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के कमांडर, सैन्य सलाहकार और मिसाइल व ड्रोन से जुड़े उपकरण भी मौजूद थे। बताया गया कि यह विमान पहले यमन की राजधानी सना में उतरने वाला था, लेकिन लैंडिंग से कुछ समय पहले सऊदी समर्थित यमनी सरकार की ओर से हवाई अड्डे पर हमले के

कभी सात अलग-अलग द्वीपों का समूह था मुंबई शहर

नई दिल्ली। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई कभी सात अलग-अलग द्वीपों का समूह था। शहर का यही ऐतिहासिक और भौगोलिक विकास आज भी मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक है। समय के साथ इन द्वीपों को आपस में जोड़कर आधुनिक मुंबई का निर्माण किया गया। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान मुंबई सात द्वीपों कोलाबा, लिटिल कोलाबा (ओल्ड वुमन आइलैंड), बॉम्बे आइलैंड, मझगांव, परेल, माहिम और वर्ली से मिलकर बना था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान बड़े पैमाने पर भूमि पुनर्ग्रहण (लैंड रिक्लेमेशन) परियोजनाएं चलाई गईं। इन परियोजनाओं के तहत समुद्र के कुछ हिस्सों को भरकर अलग-अलग द्वीपों को जोड़ा गया, जिससे धीरे-धीरे आज के मुंबई महानगर का स्वरूप तैयार हुआ। मुंबई अरब सागर के किनारे स्थित एक निचला तटीय शहर है। जिन

क्षेत्रों में आज सड़कें, इमारतें और व्यावसायिक केंद्र हैं, उनमें से कई स्थान पहले ज्वारीय खाड़ियां, दलदली भूमि या समुद्री जल से प्रभावित इलाके थे।

भूमि पुनर्ग्रहण के बाद इन स्थानों पर शहरी विकास हुआ, लेकिन उनकी प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली पहले जैसी नहीं रही। यही कारण है कि अत्यधिक वर्षा और समुद्र में ऊंचे ज्वार के दौरान कई क्षेत्रों में बारिश का पानी तेजी से समुद्र तक नहीं पहुंच पाता और जलभराव की स्थिति बन जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, हालांकि मुंबई में बाढ़ और जलभराव का कारण केवल सात द्वीपों का इतिहास नहीं है।

तेजी से बढ़ते शहरीकरण, कंक्रीट निर्माण, प्राकृतिक नालों और जलमार्गों में बदलाव, आबादी का दबाव, अपर्याप्त जल निकासी क्षमता तथा अत्यधिक वर्षा भी इस समस्या को गंभीर बनाते हैं।

इन सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव मानसून के दौरान शहर की चुनौती बढ़ा देता है। जुलाई का महीना मुंबई में सबसे अधिक वर्षा वाला माना जाता है। कई बार कुछ घंटों में ही अत्यधिक बारिश दर्ज होती है। यदि उसी समय समुद्र में हाई टाइड यानी ऊंचा ज्वार आ जाए, तो वर्षा का पानी समुद्र की ओर आसानी से नहीं निकल पाता। इससे निचले इलाकों, सड़कों और आवासीय क्षेत्रों में जलभराव की संभावना काफी बढ़ जाती है। इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ वर्षों में शहर की जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने, बड़े पंपिंग स्टेशन स्थापित करने, नालों की नियमित सफाई, बाढ़ प्रबंधन प्रणाली में सुधार और मौसम पूर्वानुमान के आधार पर त्वरित कार्रवाई जैसी कई पहल की गई हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल से रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा स्वीकार

पंजाब की राजनीति में नए समीकरणों की सुबुगबुगाहट तेज

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की जारी अटकलों के बीच रेल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से उनका त्यागपत्र तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।

रवनीत बिट्टू के इस्तीफे की संभावना लंबे समय से जताई जा रही थी, क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया था। उनके साथ ही मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को भी दोबारा राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया गया था, जिसके बाद मंत्री पद से इस्तीफे का रास्ता साफ हो गया।

रवनीत सिंह बिट्टू के इस्तीफे के साथ ही वर्ष 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के राजनीतिक समीकरणों और केंद्र सरकार में पंजाब से किसी नए चेहरे को शामिल किए जाने की चर्चाएं बेहद तेज हो गई हैं। बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बेअंत सिंह के पोते हैं और कभी राज्य कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे।

उन्होंने वर्ष 2009 में आनंदपुर साहिब तथा 2014 और 2019 में लुधियाना से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। लुधियाना से चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताते हुए राजस्थान से राज्यसभा भेजकर केंद्र में राज्य मंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा था।

राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी अब केंद्रीय स्तर पर क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर सकती है। माना जा रहा है कि पद छोड़ने के बाद रवनीत बिट्टू अब अपना पूरा ध्यान पंजाब की प्रांतीय राजनीति पर केंद्रित करेंगे और 2027 के चुनावों में लुधियाना क्षेत्र की किसी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने आधिकारिक बयान जारी कर शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में देश और विशेष रूप से अपने गृह राज्य पंजाब की सेवा करना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में सेवा, राष्ट्रवाद और विकसित भारत के संकल्प के प्रति हमेशा पूरी निष्ठा से प्रतिबद्ध रहेंगे।

अमेरिका के नए टैरिफ से भारतीय उद्योगों की बढ़ेगी चिंता

टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग क्षेत्र पर सीधा असर

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत लिए गए नए फैसले ने भारतीय निर्यातकों और व्यापारिक जगत की हलचल बढ़ा दी है। अमेरिका द्वारा सेक्शन 301 के तहत भारत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा से भारतीय वस्तुओं का अमेरिकी बाजार में मुकाबला करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह फैसला मुख्य रूप से जबरन मजदूरी (फॉर्स्ड लेबर) से जुड़े वैश्विक उत्पादन को नियंत्रित करने के तर्क के साथ लागू किया गया है।

अमेरिकी ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 301 अमेरिका को उन देशों पर आर्थिक पाबंदियां लगाने का अधिकार देता है, जिनकी नीतियां उसके उद्योगों के लिए नुकसानदेह मानी जाती हैं। इस बार ट्रंप प्रशासन ने श्रम मानकों और अनुचित उत्पादन लागत को मुद्दा बनाते हुए भारत समेत 60 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क थोपा है। हालाँकि, अमेरिका ने माना है कि भारत ने श्रम सुधारों के लिए कानूनी कदम उठाए हैं, इसीलिए उसे चीन, ब्रिटेन और जापान (जिन पर 12 .5प्रतिशत शुल्क लगा है) की तुलना में 10 प्रतिशत की कम शुल्क वाली श्रेणी में रखा गया है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, इस 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ का सबसे बड़ा असर भारत के श्रम-आधारित क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, इंजीनियरिंग सामान, रसायन और हस्तशिल्प पर पड़ेगा। अमेरिका में भारतीय सामान महंगा होने से निर्यात में कमी आ सकती है, जिससे घरेलू विनिर्माण और रोजगार पर असर पड़ने की आशंका है। इसके अलावा, भारत की सूची में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश भी शामिल हैं, जिससे इस पूरे क्षेत्र के निर्यात व्यापार पर दबाव बढ़ेगा।

सऊदी जहाज पर हमले के बाद हुदैदाह में एयरस्ट्राइक, हूतियों ने चेताया

सना। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार गहराता जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनातनी के बीच अब यमन के हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच भी सीधा टकराव सामने आया है। लाल सागर में एक सऊदी मालवाहक जहाज पर हुए हमले के बाद सऊदी अरब ने हूतियों के नियंत्रण वाले यमन के हुदैदाह शहर में हवाई हमले किए।

रूस के ड्रोनों से निपटने स्वीडन की कंपनी ने निकाला तोड़, बनाई छोटी व सस्ती मिसाइल

मास्को। यूक्रेन युद्ध और रूस के बढ़ते ड्रोन हमलों ने यूरोप के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। रूस बेहद सस्ते ड्रोनों से हमला कर रहा है, जबकि नाटो देश उन्हें गिराने के लिए अपनी फाइटर जेट्स से 10 लाख डॉलर की महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटे से मच्छर को मारने के लिए तोप चलाई जाए। अब स्वीडन की कंपनी ने ऐसी छोटी और सस्ती मिसाइल तैयार की है, जो हजारों डॉलर के ड्रोन को मारकर गिरा सकती है। इस मिसाइल का नाम क्रूगर है। इसे बनाने वाली कंपनी नॉर्डिक एयर डिफेंस का दावा है कि यह यूरोप की सबसे बड़ी रक्षा चुनौती को खत्म कर सकती है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्रूगर मिसाइल का आकार लगभग जूते के डिब्बे जितना है। इसमें एक छोटा प्रोपेलर लगा है और पहली नजर में यह किसी खिलौने जैसी लगती है, लेकिन कंपनी का कहना है कि इसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है। यह खुद दुश्मन के ड्रोन को पहचानती है। उसका पीछा करती है और सही दूरी पर पहुंचकर उसे तबाह कर देती है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि रूस सैकड़ों-हजारों सस्ते ड्रोन बना रहा है, जबकि उन्हें गिराने के लिए नाटो को लाखों डॉलर कीमत वाली मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं। कई बार 500 डॉलर का ड्रोन करोड़ों डॉलर के टैंक को नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन उसे रोकने के लिए 10 लाख डॉलर की मिसाइल दागनी पड़ती है।

यही लागत का अंतर यूरोप के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। कंपनी का दावा है कि असली युद्ध में यह विस्फोट दुश्मन के ड्रोन को पूरी तरह बर्बाद कर देगा।

नई पीढ़ी को आदेश नहीं संवाद की जरूरत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि आज की युवा पीढ़ी केवल आदेश मानने के बजाय तर्क और खुले संवाद में विश्वास रखती है।

नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में विश्व मांगल्य सभा द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम में समकालीन मातृत्व विषय पर बोलते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूली किताबों में हिंदू देवी-देवताओं के बारे में जानकारी शामिल की जानी चाहिए, ताकि बच्चों की बढ़ती जिज्ञासाओं और सवालों का सही जवाब मिल सके।

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि खासकर विदेशों में रहने वाले बच्चे अक्सर पूछते हैं कि भगवान के रूप या

स्वरूप ऐसे क्यों हैं? जब वे घर आकर ये सवाल करते हैं, तो अक्सर माता-पिता के पास भी इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता। इसलिए इन विषयों को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि बच्चों को केवल किताबों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि माता-पिता को भी अपनी जानकारी बढ़ानी होगी। आज के बच्चे हर बात का विश्लेषण करते हैं और लोजिक जानना चाहते हैं, इसलिए उनसे खुलकर बातचीत करना बेहद जरूरी है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा और सोच को प्रभावित कर यह साबित करने की कोशिश की कि हमारी परंपराएं व अध्यात्म गलत हैं और उनका विज्ञान सही है। आक्रमणों और ब्रिटिश काल के दौरान पैदा किए गए भ्रम के कारण हम अपनी ही समृद्ध विरासत को भूल गए, जिसे अब फिर से जानने और समझने का समय आ गया है।

भागवत ने मातृत्व को सृष्टि के निर्माण, पोषण और समाज की निरंतरता का मूल आधार बताया। उन्होंने कहा कि मां बच्चे की पहली गुरु होती है और बच्चे उपदेशों से ज्यादा माता-पिता के आचरण को देखकर सीखते हैं। इसलिए परिवारों को आपस में समय बिताना चाहिए।

अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मातृत्व जैसे विषय पर किसी पुरुष का बोलना अपने आप में विरोधाभासी है, क्योंकि यह पूरी तरह से महिलाओं का अधिकार क्षेत्र है। इस भव्य समापन सत्र में 900 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अग्रिम पंक्ति में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, सांसद कंगना रनौत, बांसुरी स्वराज, स्वाति मालीवाल तथा वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जैसे कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

6.7 करोड़ साल पुराना डायनासोर का कंकाल 430 करोड़ में हुआ नीलाम

वाशिंगटन। डायनासोर भले ही करोड़ों साल पहले धरती से विलुप्त हो गए हों, लेकिन आज भी उनके जीवाश्म दुनिया के सबसे कीमती वैज्ञानिक खजानों में गिने जाते हैं। अमेरिका में करीब 6 .7 करोड़ साल पुराने एक डायनासोर के कंकाल की नीलामी रिकॉर्ड 5 .01 करोड़ डॉलर यानी करीब 430 करोड़ रुपए में हुई। इसके साथ ही यह दुनिया का अब तक का सबसे महंगा जीवाश्म बन गया, लेकिन सवाल यह है कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि किसी खरीदार ने इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीलाम हुआ यह कंकाल खतरनाक डायनासोर टायरैनोसॉरस रेक्स यानी टी-रेक्स का है। टी-रेक्स करीब 6 .7 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद था।

झरनों और बादलों से घिरे पहाड़ों के लिए मशहूर है तमिलनाडु का कोडैकनाल

नई दिल्ली। वेस्टर्न घाट की ऊंचाइयों पर बसा तमिलनाडु का कोडैकनाल हिल स्टेशन अपनी घनी हरियाली, शांत नदियों, मनमोहक झीलों, कलकल करते झरनों और बादलों से घिरे पहाड़ों के लिए मशहूर है। बरसात के दिनों में इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। समुद्र तल से लगभग 2,100 मीटर की ऊंचाई पर बसा कोडैकनाल साल भर सुहावने मौसम का अनुभव कराता है, लेकिन मानसून के दौरान इसका नजारा अद्भुत हो जाता है। बारिश के मौसम में, घाटियां धुंध से ढकी रहती हैं और आसपास की हरियाली स्वर्ग जैसा अहसास कराती है।

यही वजह है कि प्रकृति प्रेमी, कपल्स और फोटोग्राफी के शौकीन बड़ी संख्या में यहां आकर इस मनमोहक दृश्य का आनंद लेते हैं। अगर आप कोडैकनाल जाते हैं, तो अपनी यात्रा में कोडैकनाल झील, कोकर वॉक, ब्रायंट पार्क, पिलर रॉक्स, सिल्वर कैस्केड वॉटरफॉल और ग्रीन वैली जैसी जगहों को जरूर शामिल करें। कोडैकनाल झील पर नौका विहार का आनंद लेना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है, खासकर जब झील के चारों ओर की पहाड़ियां बादलों से घिरी हों। कोकर वॉक पर टहलते हुए आप घाटी के शानदार नजारों का दीदार कर सकते हैं, जबकि ब्रायंट पार्क में फूलों और पौधों की विविधता मन को मोह लेती है। पिलर रॉक्स की विशाल चट्टानें और सिल्वर कैस्केड वॉटरफॉल का तेज बहाव बारिश में और भी शानदार लगते हैं। ग्रीन वैली, जिसे सूइसाइड पॉइंट भी कहा जाता है, बारिश के बाद घनी हरियाली से भर जाती है और यहां से घाटी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। अगर आपको ट्रेकिंग, साइकिलिंग या प्रकृति के बीच घूमना पसंद है, तो कोडैकनाल आपको निराश नहीं करेगा। यहां की घुमावदार सड़कें, चाय और कॉफी के बागानों के बीच बने रास्ते और शांत माहौल शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से सुकून देते हैं। बारिश के दौरान, झरने ज्यादा तेजी से बहते हैं और आसपास का प्राकृतिक नजारा और भी मनमोहक हो जाता है, जो एडवेंचर और शांति का बेहतरीन संगम प्रदान करता है। हालांकि, बारिश के दौरान घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि फिसलन और कम विजिबिलिटी की समस्या हो सकती है।

बिना सर्जरी ठीक होगा प्रोस्टेट कैंसर! फोकल थेरेपी ने डॉक्टरों को किया हैरान

नई दिल्ली। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाले सबसे आम कैंसर है। अब तक इसके इलाज के लिए सर्जरी, रेडियोथेरेपी और अन्य उपचारों का सहारा लिया जाता है।

हालांकि, इन उपचारों के साथ कई बार पेशाब पर नियंत्रण में दिक्कत या यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। ऐसे में एक नई तकनीक फोकल थेरेपी ने डॉक्टरों और मरीजों दोनों का ध्यान खींचा है।

मरीजों में यूरिन लीक और यौन क्षमता से जुड़ी समस्याएं कम देखने को मिलीं

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के तहत करीब 10 साल तक चले एक बड़े क्लिनिकल अध्ययन में करीब 3,500 प्रोस्टेट कैंसर मरीजों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन से पता चला कि सही मरीजों में फोकल थेरेपी कैंसर को नियंत्रित करने में सर्जरी और रेडियोथेरेपी जितनी प्रभावी हो सकती है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस तकनीक को प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में एक अहम विकल्प के रूप में देख रहे हैं। फोकल थेरेपी प्रोस्टेट कैंसर के इलाज का एक आधुनिक और कम इनवेसिव तरीका है। इसमें पूरे प्रोस्टेट ग्लैंड को निकालने या पूरे हिस्से पर रेडिएशन देने की बजाय डॉक्टर केवल उस छोटे हिस्से को निकालते हैं, जहां कैंसर मौजूद होता है यानी स्वस्थ ऊतकों को जितना संभव हो, सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। इस उपचार में कैंसर वाली कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए अलग-अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हाई-इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड या क्रायोथेरेपी। चूंकि इलाज सिर्फ कैंसर वाले हिस्से तक सीमित रहता है, इसलिए आसपास के सामान्य ऊतकों को कम नुकसान पहुंचता है। इसी वजह से कई मरीजों में सर्जरी की तुलना में पेशाब पर नियंत्रण खोने और यौन क्षमता से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम देखा गया है।

शोधकताओं के मुताबिक इस थेरेपी से कैंसर को नियंत्रित करने के परिणाम काफी उत्साहजनक रहे। साथ ही, मरीजों में यूरिन लीक और यौन क्षमता से जुड़ी समस्याएं सर्जरी की तुलना में कम देखने को मिलीं। विशेषज्ञों ने इन नतीजों को ह्लबेहद अच्छाह्व बताया और माना है कि भविष्य में इस थेरेपी को अस्पतालों में उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास बढ़ सकते हैं।

अभी प्रोस्टेट तक ही सीमित है

डॉक्टरों का कहना है कि फोकल थेरेपी हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं है। यह मुख्य रूप से उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है, जिनका लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर हो, यानी कैंसर अभी प्रोस्टेट तक ही सीमित हो। अगर कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल चुका है, तो इलाज की रणनीति अलग हो सकती है। फोकल थेरेपी प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में एक नई उम्मीद जरूर लेकर आई है, लेकिन यह अभी भी मरीज की स्थिति के मुताबिक चुना जाने वाला उपचार है। अगर किसी व्यक्ति में प्रोस्टेट कैंसर का पता चलता है, तो इलाज का फैसला विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह के मुताबिक ही करना चाहिए। सही समय पर जांच और उचित उपचार से इस बीमारी को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।

क्या सोनम वांगचुक और सीजेपी के बीच गहरे मतभेद सतह पर आए

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक विवाद पर दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने नया मोड़ ले लिया है। नीट पेपर लीक आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिनों का अनशन समाप्त किया है, लेकिन उनके कदम के बाद आंदोलन की अगुवाई कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और वांगचुक के बीच दूरियां साफ दिख रही हैं। उनके बीच गहरे मतभेद सतह पर आ गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता वांगचुक ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद मेदांता अस्पताल में अपना अनशन तोड़ दिया। केंद्री सरकार ने उन्हें तीन मुख्य आश्वासन दिए हैं 20 जुलाई के संसद चलो मार्च में भाग लेने वाले युवाओं पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, नीट पेपर लीक से निराश होकर आत्महत्या करने वाले छात्रों को मुआवजे पर सकारात्मक विचार किया जाएगा और देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा पेपर लीक जैसे मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा होगी। वांगचुक ने एक्स पर अपना अनशन तोड़ने का

वीडियो साझा कर लिखा, भूख का अंत, जवाबदेही की शुरूआत!

...कब तक बरकरार रख पाती है

इस बीच, प्रदर्शनकारी छात्रों को विपक्ष का पूरा समर्थन मिल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले विधेयक की घोषणा पर निशाना साधकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग की है। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि प्रधान को पद से हटाना ही केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाने वाला सबसे कड़ा कदम होगा। लेकिन वांगचुक के रुख में नरमी के बाद अब यह लड़ाई पूरी तरह से सीजेपी के कंधों पर आ गई है। यह देखना होगा कि सीजेपी बिना वांगचुक के आंदोलन की धार को कब तक बरकरार रख पाती है।

हालांकि, सीजेपी वांगचुक के समझौते से पूरी तरह सहमत नहीं दिख रही है। आंदोलन की शुरूआत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दोनों की सबसे प्रमुख मांग थी, जिसे वांगचुक ने अपने समझौते में छोड़ दिया। सीजेपी ने वांगचुक के अनशन खत्म करने के अपडेट्स और वीडियो को अपने आधिकारिक हैंडल्स से साझा नहीं किया है। सीजेपी ने साफ किया है कि उनका जंतर-मंतर पर धरना तब तक जारी रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते है। वांगचुक के अनशन वापसी से केंद्र सरकार को एक बड़ा एग्जिट रूट जरूर मिला है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। सीजेपी के आह्वान पर शुक्रवार को भी जंतर-मंतर पर हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और केंद्र सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। मध्य दिल्ली में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है। एहतियात के तौर पर मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा गया है और कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी सीमित किया गया है। यह मुद्दा संसद के मानसून सत्र में भी लगातार गूंज रहा है, जहां विपक्षी दल युवाओं की मांगों का समर्थन कर कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं।

ताजा खबर

संक्षिप्त

राज्यपाल रमन डेका से निजी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों ने की भेंट

रायपुर. राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां लोकभवन में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित प्रावधानों पर राज्यपाल से विचार-विमर्श किया। श्री डेका ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार के सबंद्ध में अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर मैट्स विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति श्री गजराज पगारिया, शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भिलाई दुर्ग के कुलाधिपति आईपी मिश्रा, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलाधिपति सुशील चंद्राकर, कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति डॉ. संदीप अरोड़ा, आईएसबीएम विश्वविद्यालय, गरियाबंद और रायपुर के कुलपति डॉ. आनंद महलवार, अंजनेय विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति श्री अभिषेक अग्रवाल, दावड़ा विश्वविद्यालय रायपुर के सीईओ चिन्मय दावड़ा, कोलंबिया विश्वविद्यालय रायपुर के प्रो. कुलाधिपति हरजीत सिंह हूरा उपस्थित थे।

कलाकारों और साहित्यकारों के सम्मान-संवर्धन की दिशा में बड़ा कदम

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन तथा कलाकारों के कल्याण के उद्देश्य से संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मंत्रालय के सभाकक्ष में 'कलाकार कल्याण कोष योजना' तथा 'अभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति योजना' के अंतर्गत सहायता एवं छात्रवृत्ति राशि के चेक वितरण का वृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के वरिष्ठ कलाकारों, साहित्यकारों तथा युवा प्रतिभाओं के सम्मान और प्रोत्साहन का भावपूर्ण वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान पद्मविभूषण स्व. डॉ. तीजन बाई अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पंडवानी कलाकार के परिजनों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य सात वरिष्ठ दिवंगत कलाकारों एवं साहित्यकारों के परिजनों को भी एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि देकर उनके कला और साहित्य के क्षेत्र में दिए गए अविस्मरणीय योगदान का सम्मान किया गया। वहीं, अभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों और विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी प्रतिभा को नई ऊर्जा और प्रोत्साहन दिया गया। कार्यक्रम में सहायता एवं छात्रवृत्ति राशि के चेक संस्कृति विभाग के सचिव एस. भारतीदासन, फिल्म विकास निगम की अध्यक्षा सुश्री मोना सेन तथा सिंधी अकादमी की अध्यक्षा श्रीमती सुषमा जैदानी के हाथों हितग्राहियों एवं दिवंगत कलाकारों के परिजनों को प्रदान किए गए। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कला और साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए युवा पीढ़ी को उनकी परंपरा आगे बढ़ाने का संदेश दिया।संस्कृति विभाग के सचिव एस. भारतीदासन ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ लोककला, लोक साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध प्रदेश है। कलाकारों और साहित्यकारों ने अपने जीवनभर समाज को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने का कार्य किया है।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने जेलों में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा

रायपुर. लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने प्रदेश के विभिन्न जेलों में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पीडब्लूडी मुख्यालय 'निर्माण भवन' में आज आयोजित बैठक में जिलों के कार्यपालन अभियंताओं, जेल अधीक्षकों और ठेकेदारों को बेहतर समन्वय बनाकर कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक श्री हिमांशु गुप्ता और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी भी बैठक में शामिल हुए। लोक निर्माण विभाग के विभिन्न संभागों के कार्यपालन अभियंता, ठेकेदार और जेल अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक में जुड़े। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में प्रदेश की विभिन्न जेलों में निर्माणाधीन बैरकों, बाउंड्रीवॉल्स, शौचालयों और वॉच टॉवर्स के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ ही सभी जेलों के अधीक्षकों से निर्माण कार्यों की गति और गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को कार्यस्थलों का नियमित दौरा कर कार्यों की कड़ाई से मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों को भी निर्माण सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूरा करने को कहा। श्री बंसल ने कार्यपालन अभियंताओं और जेल

अधीक्षकों को सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए जेल परिसर के भीतर निर्माण सामग्रियों के परिवहन की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने जेल अधीक्षकों को श्रमिकों को रोज काम के लिए पर्याप्त समय देने को कहा। जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक श्री हिमांशु गुप्ता ने बैठक में कहा कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रह रहे हैं। नए बैरकों के निर्माण और मौजूदा सुविधाओं के विस्तार से राहत मिलेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के मैदानी अधिकारियों, जेल अधीक्षकों और ठेकेदारों को तेज गति से काम कर कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में रायपुर केन्द्रीय जेल में पार्किंग शेड, पाठशाला शेड, मुलाकातियों-परिजनों के लिए शेड व शौचालय निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बिलासपुर के नगोई में 1500 आवास क्षमता के विशेष जेल, जिला जेल धमतरी और गरियाबंद में बाउंड्रीवॉल, जिला जेल जांजगीर, रामानुजगंज, सूरजपुर, कांकेर, संजारी-बालोद तथा उप जेल सारंगढ़ में बैरक निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। विभागीय सचिव ने कवर्धा उप जेल में मुख्य दीवार की ऊंचाई बढ़ाने के कार्य, केन्द्रीय जेल अंबिकापुर और जगदलपुर में कैदियों के लिए बैरक एवं शौचालय निर्माण, जिला जेल दंतेवाड़ा में शौचालय निर्माण, जिला जेल सुकमा की मुख्य दीवारों के चारों ओर कंसर्टीना वायर फेंसिंग तथा वॉच टॉवर निर्माण एवं उप जेल बीजापुर में वॉच टॉवर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

धमतरी जिले में 3.92 करोड़ रुपए के बोनस वितरण के साथ खुशहाली की नई बयार

तेंदूपत्ता संग्राहकों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की ओर छत्तीसगढ़

रायपुर. छत्तीसगढ़ के वनाश्रित अंचलों में जीवन-यापन करने वाले तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य शासन ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। लंबे समय से प्रतीक्षित प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) की राशि अब सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा रायपुर स्थित कृषि मण्डपम में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के दौरान वर्ष 2023 के तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बोनस वितरण का शुभारंभ करने के बाद धमतरी जिले सहित प्रदेश भर में ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया बेहद तेजी से पूरी की जा रही है।

पारंपरिक आजीविका का स्थायी और मजबूत आधार

राज्य शासन का यह प्रयास केवल मौसमी रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पारंपरिक आजीविका को एक स्थायी और मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करने की दिशा में एक समग्र रणनीति का हिस्सा है।

3.92 रुपए करोड़ का स्वीकृत बोनस और प्रत्यक्ष हस्तांतरण

जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, वनमंडल धमतरी के प्रबंध संचालक एवं वनमंडलाधिकारी के अनुसार, वर्ष 2023 के तेंदूपत्ता विक्रय से लाभ अर्जित करने वाली जिले की 25 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के 212 फड़ों से जुड़े ग्रामों के 23,723 संग्राहक परिवारों के लिए कुल 3.92

करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक स्वीकृत किया गया है।

पारदर्शिता के साथ त्वरित भुगतान

20 जुलाई 2026 तक 3.84 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है। पात्र शेष हितग्राहियों को भी त्वरित प्रक्रिया के तहत राशि सीधे स्थानांतरित की जा रही है। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित की है, जिससे संग्राहकों की आय में प्रत्यक्ष एवं उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

धमतरी जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण के आंकड़ों पर नज़र डालें तो वर्ष 2026 के लिए 26 हजार 800 मानक बोरा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके विरुद्ध 26 हजार 550 संग्राहकों के सम्मिलित योगदान से 23 हज़ार 751 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया, जो कि कुल लक्ष्य का लगभग 88.70 प्रतिशत है। इस संग्रहण कार्य के बदले संग्राहकों को 13.07 करोड़ रुपए से अधिक का पारिश्रमिक भुगतान सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

वहीं, इससे पिछले वर्ष 2025 में जिले के 27 हजार 887 संग्राहकों ने भाग लिया था, जिनके द्वारा 25 हजार 275.63 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित किया गया था। इस कार्य के लिए संग्राहकों को 13.90 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक पूर्ण रूप से वितरित किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022 के बोनस के रूप में भी 24 हजार 529 संग्राहकों को 6.33 करोड़ रुपए का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का दायरा

तेंदूपत्ता संग्राहकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए केवल वित्तीय प्रोत्साहन ही नहीं, बल्कि कई सामाजिक सुरक्षा और सुविधामूलक योजनाएं भी पूरी निष्ठा के साथ संचालित की जा रही है। वर्ष 2024-25 में 27 हजार 532 महिला संग्राहकों को चरण पादुकाएं वितरित की गईं। वहीं, सत्र 2025-26 में 28 हजार 723 पुरुष संग्राहकों को चरण पादुकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। संघ संचालित इस योजना के तहत मई 2026 तक प्राप्त 258 मामलों में से 205 का निराकरण कर 24.60 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

राजमोहिनी देवी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 392 में से 339 प्रकरणों को स्वीकृति देते हुए 4.43 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित कर संकट की घड़ी में परिवारों को संबल प्रदान किया गया।

वनधन विकास, शिक्षा और पीएम जनमन से बदली तस्वीर

मुख्य सचिव ने SASCI 2026-27 के तहत सुधार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की

रायपुर. मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना 2026-27 के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे सुधार कार्यों एवं उनके क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से विभागवार मासिक कार्ययोजना तैयार कर उसके अनुसार कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा, ताकि योजना के तहत तय लक्ष्यों को समय पर हासिल किया जा सके। बैठक में राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना 2026-27 के तहत जारी दिशा-निर्देशों एवं विभिन्न परिचालन गाइडलाइंस के अनुरूप विभागवार सुधार कार्यों की प्रगति, अब तक की उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध लक्ष्य-पूर्ति तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। बैठक में वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव मुकेश कुमार, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव सुश्री आर.शंगीता, राजस्व विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. सारांश मित्तर, वित्त विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल श्री विवेक आचार्य सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

40 शिल्पियों को वितरित किए आधुनिक टूल किट

रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत ने गुरुवार को कोंडागांव स्थित शिल्पनगरी का दौरा कर शिल्पकारों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जिले के 40 शिल्पियों को आधुनिक टूल किट वितरित किए। इसमें 20 बेलमेटल एवं 20 लौहशिल्प के शिल्पकार शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन स्थानीय कला, संस्कृति और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण, संवर्धन तथा शिल्पकारों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोंडागांव की शिल्पकला जिले की विशिष्ट पहचान है, जिसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि शिल्पकार अपनी कलाकृतियों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए शबरी एम्पोरियम एक माध्यम है। साथ ही आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण लेकर बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करें, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि शिल्पकारों को केवल प्रोत्साहन देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें आधुनिक बाजार से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी आवश्यक है।

सीएम ने दी जनकल्याणकारी की जानकारी

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में संचालित बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत बालिकाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सूरजपुर जिले के विकासखंड प्रतापपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंछीडांड़ (केरता) में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव, महिला एवं बाल अधिकार, लैंगिक समानता, वित्तीय साक्षरता तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें सुरक्षित एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, घरेलू हिंसा से संरक्षण, महिला उत्पीड़न की रोकथाम, मासिक धर्म स्वच्छता, बाल विवाह के दुष्परिणाम तथा बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी दी। विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 तथा आपातकालीन सेवा 112 का उपयोग करने के बारे में भी बताया गया।

महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाया कदम

बलौदा बाजार। जिला प्रशासन द्वारा गृहणी महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा जनपद पंचायत बलौदा बाजार के तहत ग्राम लाहोद में महिलाओं को पैरा से आर्ट बनाने की कला का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं उन्हें राखी और बैज बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसका सार्थक परिणाम सामने आ रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर लगभग 150 महिलाएं अब पैरा आर्ट के साथ आने वाले रक्षाबंधन त्योहार और स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए बड़ी मात्रा में धान के साथ चांवल के दाने से राखी के साथ बैज बना रही है। वहीं प्रशासन द्वारा महिलाओं की ओर से बनाए गए राखी और बैज को बिक्री करने का भी इंतजाम किया जा रहा है। राखी, बैज और पैरा आर्ट बना रही महिलाओं ने बताया कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद वह अपने घर के काम को पूरा करने के बाद राखी बैज और पैरा आर्ट बना रही है जिसे वह आने वाले त्योहार में बिक्री करेंगी। शासन द्वारा हम घरेलू महिलाओं के लिए यह बहुत अच्छी व्यवस्था है कि हम घर पर रहकर घर की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेंगे। उन्होंने शासन का आभार जताते हुए कहा कि यह योजना लाई है और जिस पैरा को हम लोग फेंक देते थे वह अब हमारे आय का जरिया साबित हो रहा है। जनपद पंचायत बलौदा बाजार के सीईओ एफ सी पटेल ने बताया कि शासन द्वारा लाहोद में दस दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 150 महिलाओं ने पैरा से आर्ट बनाने की कला के साथ ही धान और चांवल से राखी बनाना सीखा है। निश्चित ही इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा और वे आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगी और आत्मनिर्भर बनेगी।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन आमंत्रित

रायपुर. बच्चों की असाधारण प्रतिभा, नवाचार, साहस और सामाजिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों, अभिभावकों, शिक्षण संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों से अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश का सर्वोच्च बाल सम्मान माना जाता है, जो उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। विभागीय जानकारी के अनुसार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं।

दिल्ली में पत्रकारों पर हमले की छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रेस क्लबों ने की कड़ी निंदा

रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने हमलों के विरोध में निंदा प्रस्ताव रखा

कोरबा। कोरबा प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रेस क्लबों के अध्यक्षों ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर में कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ हुई हिंसक घटनाओं की एक स्वर में कड़ी निंदा की तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। बैठक में रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने पत्रकारों पर हो रहे हमलों के विरोध में निंदा प्रस्ताव रखा।

प्रस्ताव का बिलासपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजीत मिश्रा, कोरबा प्रेस क्लब के अध्यक्ष नौशाद खान ने समर्थन किया , इस मौके पर बिलासपुर, कोरबा के वरिष्ठ पत्रकारों और प्रेस क्लब पदाधिकारियों कवरेज के दौरान पत्रकारों पर हिंसा को चिंता जनक बताया और सभी प्रेस क्लब अध्यक्षों ने सर्वसम्मति बना कर ऐसी घटना की निंदा करने का सुझाव रखा। बैठक में वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि जंतर-मंतर में कवरेज कर रहे वरिष्ठ पत्रकारों रोहित रंजन, देव कोटक, शेफाली, आर्यन आनंद, लोकेश ठाकुर एवं अन्य मीडियाकर्मियों के साथ मारपीट, मोबाइल एवं घड़ी छीनने, कपड़े फाड़ने तथा पत्रकारिता के उपकरणों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं न केवल निंदनीय हैं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी सीधा आघात हैं। बैठक में इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की गई कि देशभर में पत्रकारों के साथ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका सत्य को समाज तक पहुंचाने की है। ऐसे में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे पत्रकारों पर हमला किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने कहा कि पत्रकारों पर हमला केवल किसी व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने का प्रयास है। ऐसी घटनाओं के दोषियों पर त्वरित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी पत्रकारों को डराने या सच की आवाज दबाने का दुस्साहस न कर सके।बैठक में प्रस्तावित निंदा प्रस्ताव की जानकारी भिलाई प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल गुप्ता, राजनांदगांव प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरि, दुर्ग प्रेस क्लब के अध्यक्ष संतोष मिश्रा तथा जगदलपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनीष गुप्ता और कांकेर प्रेस क्लब अध्यक्ष योगेश सिन्हा को भी दी गई सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। सभी प्रेस क्लबों ने अपने-अपने प्रेस क्लब में भी संबंध में प्रस्ताव पारित करने की भी बात कही है,, चर्चा में शामिल प्रेस क्लब अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा लोकतंत्र की सुरक्षा से जुड़ा विषय है।

पत्रकारों के साथ हिंसा, धमकी और भय का वातावरण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख प्रेस क्लब पीड़ित पत्रकारों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं और केंद्र तथा दिल्ली प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध शीघ्र एवं कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं।

कोरबा में आयोजित इस बैठक में कोरबा प्रेस क्लब के अध्यक्ष नौशाद खान रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी,बिलासपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजीत मिश्रा सहित रायपुर प्रेस क्लब कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव भूपेश जांगड़े के साथ कोरबा प्रेस क्लब के संरक्षक कमलेश यादव, वरिष्ठ पत्रकार एवं पदाधिकारी गण राजकुमार शाह , राकेश श्रीवास्तव , रमेश राठौड़ , दिनेश राज , कृष्णा राठौर, ई जयंत, सादिक शेख, आकाश शर्मा , बिलासपुर प्रेस क्लब पूर्व अध्यक्ष, वीरेंद्र गहवाई, निर्मल माणिक, बिलासपुर प्रेस क्लब उपाध्यक्ष विजय क्रांति तिवारी, सचिव संदीप करिहार, कोषाध्यक्ष किशोर कुमार सिंह, सह सचिव हरिकृष्ण गंगवानी, कैलाश यादव मौजूद थे।

मांगें पूरी नहीं होने पर फिर सड़क पर उरतने की दी चेतावनी

अतिथि शिक्षकों की हड़ताल खत्म, सरकार से आश्वासन के बाद लिया फैसला

दुर्ग। 23 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अतिथि शिक्षकों ने आखिरकार अपना आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित किया गया है। हालांकि अतिथि शिक्षकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 5 सितंबर 2026 तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे एक बार फिर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।

दुर्ग में प्रेसवार्ता कर अतिथि शिक्षक संघ ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। शिक्षकों ने कहा कि वे आंदोलन नहीं करना चाहते थे, लेकिन 2016 से मिल रहा मानदेय आज की महंगाई के दौर में उनके लिए बेहद कम है। उनका कहना है कि कई शिक्षक 25 किलोमीटर तक पैदल चलकर और नक्सल

प्रभावित इलाकों में जान जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ाने पहुंचते हैं। अतिथि शिक्षकों का दावा है कि उनके प्रयासों से दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नियमित शिक्षकों की तुलना में बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है। नियमित शिक्षकों को करीब एक लाख रुपये और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों को 38 हजार रुपये तक मिलते हैं, जबकि अतिथि शिक्षकों को महज 20 हजार रुपये दिए जाते हैं। शिक्षकों ने मातृत्व अवकाश, सामान्य छुट्टियों और पूरे 12 महीने के वेतन की मांग भी उठाई।

सालभर काम के बाद भी साढ़े 10 माह का मानदेय देने का आरोप

अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि 12 महीने काम लेने के बावजूद उन्हें केवल साढ़े दस महीने का मानदेय दिया जाता है।सरकार की ओर से वेतन वृद्धि, 13 सीएल, 12 महीने का मानदेय और भविष्य में नियमितीकरण को लेकर संकेत मिलने के बाद शिक्षकों ने फिलहाल आंदोलन स्थगित किया है। हालांकि पुलिस कार्रवाई और कथित बदसलूकी को लेकर शिक्षकों ने नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कर दिया है कि 5 सितंबर तक अगर उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं हुआ तो यह आंदोलन एक बार फिर सड़कों पर दिखाई देगा।

महत्वपूर्ण ख़बर

अफगानिस्तान की मेजबानी में टी20 सीरीज खेल सकती है भारतीय टीम

- मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम सितंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस सीरीज की मेजबानी पहली बार अफगान टीम करेगी। क्रिकेट प्रशंसक इस सीरीज का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। ये सीरीज दिल्ली के प्रतिष्ठित अरुण जेटली स्टेडियम में 13, 15 और 17 सितंबर को खेली जा सकती है हालांकि अभी इन तारीखों और स्थानों की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। यह सीरीज कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी क्योंकि यह पहला अवसर होगा जब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम भारत में ही भारत की मेजबानी करेगी।

गौरतलब है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम भारत को अपने घरेलू मैदान के तौर पर इस्तेमाल करती आ रही है। पिछले कुछ साल में अफगानिस्तान ने अपने कई घरेलू मैच लखनऊ, देहरादून और ग्रेटर नोएडा में खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने विभिन्न देशों की टीमों की मेजबानी की पर इनमें से कोई भी मुकाबला भारत के खिलाफ नहीं खेला था।

कॉमनवेल्थ गेम्स: तैराक श्रीहरि नटराज सेमीफाइनल में, 50 मीटर बैकस्ट्रोक हीट में 25.52 सेकंड का समय निकाला

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के 50 मीटर बैकस्ट्रोक हीट में 25.52 सेकंड का समय निकाला

ग्लासगो। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन शुक्रवार को भारत के लिए अच्छी शुरूआत रही। स्विमर श्रीहरि नटराज पुरुष 50 मीटर बैकस्ट्रोक के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं।

वहीं, पैरा स्विमिंग के पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13 वर्ग में कार्तिक (आरवीबीबीके) बुडिगिना और अली इमाम ने फाइनल के लिए क्वॉलिफाई कर लिया है। स्विमिंग में श्रीहरि नटराज ने 50 मीटर बैकस्ट्रोक हीट में 25.52 सेकेंड का समय निकाला। वह अपनी हीट में पांचवें और ओवरऑल 14वें स्थान पर रहे, जिससे उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बना ली। हालांकि दिन के पहले मेडल इवेंट पैरा पावरलिफ्टिंग पुरुष लाइटवेट वर्ग में भारत को मेडल नहीं मिला। अशोक कुमार मलिक चौथे और परमजीत कुमार छठे स्थान पर रहे।

पुरुष लाइटवेट फाइनल में नौ बार के राष्ट्रीय चैंपियन अशोक कुमार मलिक ने पहली कोशिश में 195 किलोग्राम वजन उठाया। दूसरी कोशिश में उन्होंने 200 किलोग्राम की पर्सनल बेस्ट लिफ्ट

सफलतापूर्वक पूरी और 143.8 अंक हासिल किए। हालांकि तीसरी कोशिश में 205 किलोग्राम नहीं उठा सके और चौथे स्थान पर रहे। परमजीत कुमार ने पहली कोशिश में 176 किलोग्राम वजन उठाकर 135.6 अंक हासिल किए। इसके बाद उन्होंने दूसरी और तीसरी दोनों कोशिशों में 179 किलोग्राम उठाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बार असफल रहे। वह 135.6 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहे।

अशोक 200 किलोग्राम की पर्सनल बेस्ट लिफ्ट के बावजूद पदक से चूके

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन पैरा पावरलिफ्टिंग के पहले मेडल इवेंट में भारत पदक से चूक गया। पुरुष लाइटवेट फाइनल में अशोक कुमार मलिक ने पहली कोशिश में 195 किलोग्राम वजन उठाया। दूसरी कोशिश में उन्होंने 200 किलोग्राम की पर्सनल बेस्ट लिफ्ट सफलतापूर्वक पूरी और 143.8 अंक हासिल किए। तीसरी कोशिश में 205 किलोग्राम उठाने में असफल रहे और चौथे स्थान पर रहे। परमजीत कुमार ने पहली कोशिश में 176 किलोग्राम वजन उठाकर 135.6 अंक हासिल किए। इसके बाद दूसरी और तीसरी दोनों कोशिशों में 179 किलोग्राम उठाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बार असफल रहे। वह सातवें स्थान पर रहे।

भारतीय जूडो टीम को बड़ा झटका, तुलिका मान सस्पेंड

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की रजत पदक विजेता जूडो का तूलिका मान को पिछले 12 महीनों में तीन बार ह्वेयरअबाउट्स फेलियरह्न के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इसके चलते उन्हें ग्लासगो में चल रहे मौजूदा संस्करण से बाहर कर दिया गया है। तुलिका मान ने 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में +78 किलोग्राम वर्ग में रजत रजत पदक जीता था और इस बार भी उनसे पदक की मजबूत उम्मीद थी। एक जूडो कोच ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, उन्होंने 12 महीने के भीतर तीन बार वेयरअबाउट्स फेलियर किया है और नाडा ने उन्हें नोटिस भेजा है। इसलिए उन्हें टीम से हटा दिया जाएगा।

भारत में एक एशेज टेस्ट के आयोजन पर विचार कर रहा सीए

सिडनी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) अब भारत में प्रतिष्ठित एशेज सीरीज का एक मैच आयोजित करने पर विचर कर रहा है। इससे पहले उसने घरेलू बिग बैश लीग (बीबीएल) का एक मैच भारत में आयोजित करने का फैसला किया था। सीए के मुख्य कार्यकारी टॉड ग्रीनबर्ग ने संकेत दिया है कि बोर्ड इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इससे विश्व स्तर पर क्रिकेट में भारत की बढ़ती साख का भी अंदाजा होता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित मुकाबले एशेज के भारत में आयोजन से भविष्य में एक बड़ा बदलाव आ सकता है।

ग्रीनबर्ग का यह बयान ऐसे समय आया है जब सीए भारतीय बाजार में अपनी पैठ मजबूत करने में लगा है। इसी साल 12 दिसंबर को बीबीएल मैच का आयोजन चेन्नई में होगा। वहीं अब एशेज टेस्ट की संभावना भारत की कारोबार क्षमता को दिखाती है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट दर्शक वर्ग वाले इस राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक महामुकाबला न केवल जबरदस्त जनहित पैदा करेगा, बल्कि नए और बड़े व्यावसायिक अवसर भी खोलेगा, जिससे दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड को फायदा होगा।

टॉड ग्रीनबर्ग ने एक साक्षात्कार में कहा कि विचार को लेकर वह गंभीर हैं। उन्होंने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) दोनों के साथ अपने मजबूत संबंधों का हवाला दिया। ग्रीनबर्ग ने कहा, ईसीबी और बीसीसीआई के साथ हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, और निश्चित रूप से भारत में कुछ क्षेत्रों में और अधिक सामग्री डालने के अवसर हैं। अभी हम इसकी योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड टेस्ट भारत में करवाने पर विचार

मेलबोर्न। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा है कि भविष्य में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भारत में टेस्ट मैच करवाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में क्रिकेट के लिए बड़े मौके हैं, हालांकि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। ग्रीनबर्ग ने कहा, हमें सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए। ईसीबी और बीसीसीआई दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। भारत में क्रिकेट का नया कंटेंट ले जाने के मौके हैं। अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट क्रिकेट मजबूत स्थिति में है और इसे आगे बढ़ाना जरूरी है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का व्यस्त कैलेंडर सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ग्रीनबर्ग ने कहा, साल में सिर्फ 365 दिन होते हैं। जितना क्रिकेट और कंटेंट हम देना चाहते हैं, उसके लिए शायद एक-दो महीने और चाहिए।

टॉड ग्रीनबर्ग बोले, भारत बड़ी मार्केट, संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले

मां की विरासत, बेटे का विश्व कप: यशदीप सिवाच की अनूठी यात्रा

नई दिल्ली। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व सदस्य रही प्रीतम रानी सिवाच का बेटा भी अब भारतीय हॉकी टीम की ओर से खेलता नजर आयेगा। प्रीतम ने साल 1998 में नीदरलैंड में विश्व कप खेला था। वहीं अब उनके बेटे यशदीप को नीदरलैंड और बेल्जियम में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था। जिससे बाद से ही परिवार में उत्साह का माहौल है।

यशदीप के लिए नीदरलैंड और बेल्जियम में आगामी विश्व कप केवल एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि भावनाओं और पारिवारिक विरासत से जुड़ा एक गहरा अनुभव है। इसका कारण है कि उनकी मां प्रीतम रानी की कप्तानी में 28 साल पहले भारतीय टीम ने नीदरलैंड के यूट्रेक्ट में ही विश्व कप खेला था। इसी कारण उनकी मां भी भावुक हैं। वे 26 वर्षीय यशदीप के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करना इसी कारण और भी खास हो गया है।

यूट्रेक्ट विश्व कप में भले ही भारतीय महिला टीम बारहवें स्थान पर रही थी, लेकिन प्रीतम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ दो गोल दागे थे। यशदीप बताते हैं कि बचपन से ही वे अपनी मां की एक्शन तस्वीरों, टूर्नामेंट और टीम फोटो वाली एल्बम देखते आए हैं, जिसने शायद उन्हें हॉकी स्टिक थामने के लिए प्रेरित किया। कभी तैराकी के शौकीन रहे यशदीप ने अपने माता-पिता के साथ राष्ट्रीय चैंपियनशिप और दिल्ली में 2010

का विश्व कप भी देखा था।

यशदीप ने कहा, मम्मी ने मुझसे काफी अनुभव साझा किए हैं। उनके पास पूरी एल्बम है जिसमें एक्शन पिक्चर, टूर्नामेंटों के फोटो, साथी खिलाड़ियों के फोटो हैं। मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। वह बताते हैं कि जब वह छोटे थे तब उनकी मां लंबे समय तक राष्ट्रीय शिविरों में रहती थीं, और उस समय वीडियो कॉल जैसी सुविधाएं नहीं होती थीं। उनके पिता और दादा-दादी ने पूरा ध्यान रखा, लेकिन मां की याद आने पर पिता उन्हें वीकेंड पर पटियाला या आसपास के शिविरों में ले जाते थे। टीम के बाहर खेलने जाने पर पिता उन्हें हवाई अड्डे तक ले जाते, और एक बार ओलंपिक क्वालीफायर टूर के लिए मां को जाते समय यशदीप उनके साथ होटल में भी रहे थे। तब तो उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन अब, राष्ट्रीय शिविर में आने के बाद, उन्हें अपनी मां की कड़ी मेहनत, कुर्बानियों और इतने साल लगातार शीर्ष स्तर पर खेलने के लिए मानसिक व शारीरिक फिटनेस बनाए रखने का महत्व अधिक समझ आता है।

हॉकी यशदीप के खून में है, क्योंकि उनके पिता कुलदीप भी हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं और अब एक मशहूर कोच हैं, जो हरियाणा में अपनी पत्नी के साथ प्रीतम सिवाच अकादमी चलाते हैं। चोट के कारण उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का सपना हालांकि अधूरा रह गया। उनकी बहन कनिका भी जूनियर राष्ट्रीय टीम में खेल चुकी हैं और अब सीनियर टीम में पदार्पण की दहलीज पर हैं। सिवाच परिवार के लिए यह विश्व कप काफी मायने रखता है और यशदीप पोडियम पर रहकर अपने माता-पिता का अधूरा सपना पूरा करना चाहते हैं। प्रीतम दिग्गज मिडफील्डर रही हैं और कनिका फॉरवर्ड खेलती हैं, लेकिन यशदीप को गोल करने से ज्यादा बचाने में मजा आता है। वह ऑस्ट्रेलिया में छह महीने क्लब हॉकी खेल चुके हैं और विश्व कप को लेकर बिल्कुल दबाव में नहीं हैं।

कारोबार

सोने-चांदी में आई बड़ी गिरावट : क्यों आई कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट ?

ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में बढ़ती अस्थिरता का असर अब भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ दिखाई देने लगा है.

शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. जहां सोना प्रति 10 ग्राम करीब 2,000 रुपए सस्ता हो गया, वहीं चांदी की कीमत में 5,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक की कमी देखने को मिली. कारोबारियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती अनिश्चितता और निवेशकों की मुनाफावसूली के कारण घरेलू बाजार में भी बिकवाली का दबाव बढ़ा.

राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव घटकर 1 लाख 47 हजार 200 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. इससे पहले यह 1 लाख 49 हजार 200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. यानी लगातार दूसरे कारोबारी दिन सोने में कमजोरी देखने को मिली. वहीं चांदी की कीमत भी गिरकर 2 लाख 24 हजार 700 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई. पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव 2 लाख 29 हजार 700 रुपए प्रति किलोग्राम था. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है. ऐसे माहौल में निवेशकों ने सोने और चांदी में मुनाफावसूली शुरू कर दी, जिसका सीधा असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा. इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर खरीदारी कमजोर रहने से भी कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव बना रहा. दिलचस्प बात यह रही कि वैश्विक बाजार में हाजिर सोने में हल्की मजबूती देखने को मिली. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना लगभग

4,063 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया, जबकि चांदी में भी करीब दो प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. इसके बावजूद भारतीय बाजार में गिरावट बनी रही। विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू बाजार में निवेशकों की रणनीति और स्थानीय मांग की कमजोरी ने वैश्विक तेजी का असर सीमित कर दिया.

भूराजनीतिक तनाव भी बना बड़ी वजह

कमोडिटी विश्लेषकों के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक व्यापार को लेकर बढ़ती अनिश्चितता ने वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ा दी है. निवेशकों का रुझान लगातार बदल रहा है, जिससे सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं में भी तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां इसी तरह बनी रहीं तो आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार-चढ़ाव संभव है.

लखनऊ और पटना में क्या रहे भाव? दल्ली की तुलना में लखनऊ में सोने की कीमत कुछ कम दर्ज की गई. यहां 24 कैरेट सोना 1 लाख 44 रुपए 480 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता रहा, जबकि चांदी का भाव 2 लाख 39 रुपए 900 प्रति किलोग्राम रहा. वहीं बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट सोने का भाव 1 लाख 43 हजार 240 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा. चांदी की कीमत यहां करीब 2.45 लाख रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई.

खरीदारों के लिए क्या है संकेत?

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल निवेशकों को जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय अंतरराष्ट्रीय बाजार, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम पर नजर बनाए रखनी चाहिए. यदि बाजार में अस्थिरता जारी रहती है तो सोने और चांदी की कीमतों में आगे भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. वहीं, लंबे समय के निवेशकों के लिए गिरते भाव खरीदारी का अवसर भी साबित हो सकते हैं.

होंडा ने पेश किया 10 नए टू-व्हीलर का मेगा पोर्टफोलियो, 7 बिल्कुल नए मॉडल शामिल

नई दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने शुक्रवार को भारतीय बाजार के लिए 10 नई मोटरसाइकिलों और स्कूटरों का विस्तारित पोर्टफोलियो पेश किया जिनमें सात बिल्कुल नए मॉडल हैं, जबकि तीन मॉडल नए रंग विकल्पों के साथ अपडेट किए गए हैं।

कंपनी ने बताया कि यह लाइनअप क्रूज़िंग, एडवेंचर टूरिंग, रोडस्टर, लाइफस्टाइल राइडिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक जैसे विभिन्न सेगमेंट्स को कवर करता है। इन मॉडलों का स्थानीयकरण कंपनी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे देश में उत्पाद विकास, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं को और मजबूत किया जायेगा। साथ ही, ग्राहकों को होंडा की वैश्विक तकनीकों तक अधिक पहुंच मिलेगी ।

नए मॉडलों में होंडा एडीवी 160, होंडा सीबी 500, होंडा रिबेल 300, होंडा रिबेल 500, होंडा एक्सआर 300एल तथा होंडा एक्सआर 300 रैली मोटरसाइकिल और होंडा क्यूसी3 स्कूटर शामिल हैं। वहीं, होंडा सीबी350 रेंज में नये रंग विकल्पों के साथ तीन नये मॉडल पेश किया गए हैं। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्सुत्सुमु ओतानी ने कहा, भारत होंडा के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। यह 10-उत्पादों का पोर्टफोलियो ग्राहकों को व्यापक परिवहन समाधान प्रदान करता है। इसमें आधुनिक पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और फ्लेक्स-फ्यूल के विकल्प शामिल हैं। साथ ही, हम मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के अपने संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत वैश्विक उत्पादन और निर्यात केंद्र के रूप में और अधिक मजबूत होगा।

8वें वेतन आयोग की बैठकें अगस्त में, कर्मचारियों को मिली राहत

महत्वपूर्ण बैठकें 7 अगस्त और 10 अगस्त को आयोजित की जाएंगी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। आयोग ने दिल्ली में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स यूनियनों के साथ आगामी बैठकों का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये महत्वपूर्ण बैठकें 7 अगस्त और 10 अगस्त, 2026 को आयोजित की जाएंगी, जिनमें केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान, भत्तों और पेंशन से संबंधित विभिन्न सुझावों पर गहन चर्चा की जाएगी। इस घोषणा से देश के लगभग 1.19 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को राहत मिली है, जो लंबे समय से आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। आयोग ने उन सभी कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों को एक और अवसर प्रदान किया है, जिन्होंने पूर्व में अपना मेमोरेंडम जमा कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश अभी तक

आयोग के साथ उनकी बैठक नहीं हो पाई थी। ऐसे संगठन इन आगामी बैठकों में शामिल होने के लिए 31 जुलाई, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय उन्हें अपनी मेमो आईडी के साथ अपॉइंटमेंट की मांग करनी होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर सीमित विचार किया जाएगा, इसलिए सभी संगठनों को निर्धारित तिथि से पहले प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। 8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मौजूदा वेतन, भत्तों और पेंशन व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करना है। इस प्रक्रिया के तहत आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और फेडरेशनों से सुझाव एकत्र कर रहा है। दिल्ली में होने वाली ये बैठकें इसी व्यापक विचार-विमर्श प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जहाँ कर्मचारी संगठन सीधे आयोग के समक्ष अपनी मांगों और सुझावों को प्रस्तुत कर सकेंगे। इन्हीं सुझावों के अध्ययन के बाद आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा, जिन्हें बाद में केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा, और इन्हीं के आधार पर भविष्य के नए वेतनमान व अन्य लाभ तय होंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली में होने वाली बैठकें केवल प्रारंभिक चरण हैं। इसके बाद आयोग की योजना अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कर्मचारी संगठनों के साथ इसी तरह की बातचीत आयोजित करने की है, ताकि अधिकतम संगठनों की राय को अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जा सके। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (एआईएनपीएसएफ) सहित कई कर्मचारी संगठनों ने पहले आयोग से जल्द बैठकें आयोजित करने की मांग की थी, और इस नए शेड्यूल का स्वागत किया है।

युवाओं के हित में कार्य कर रही है सरकार : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के हित में निरंतर कार्य कर ही है। विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था से युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर दिलवाने का प्रयास है।

मेडिकल कॉलेज भी तेज गति से प्रारंभ हो रहे हैं। इससे आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 34 है, जो दो वर्ष में बढ़कर 52 हो जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पन्ना में हेलीपेड पर टीवी चैनल प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2002-03 में प्रदेश में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज थे। मेडिकल कॉलेज की सीट संख्या भी मात्र 500 थी, जो वर्तमान में बढ़कर साढ़े पांच हजार हो गई है। आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज की सीट्स 10 हजार हो जाएंगी। यह राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है और इस नाते चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

प्रदेश में 10 हजार हो जाएंगी मेडिकल कॉलेज की सीट्स

पन्ना मेडिकल कॉलेज

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसके पूर्व पन्ना में आयोजित लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम में जानकारी दी कि अगले वर्ष पन्ना मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाएगा। पीपीपी मोड पर बनने वाले चिकित्सा महाविद्यालय भवन का कार्य तेजी से चल रहा है। वर्तमान में पन्ना के निवासियों को सतना मेडिकल कॉलेज और छतरपुर में विशेष चिकित्सा के लिए जाना होता है।

युवाओं के लिए मध्यप्रदेश के 4 महानगरों में प्रारंभ होंगे फास्ट ट्रैक कोर्टः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पन्ना में पर्यटन बढ़ाने के लिए नदी पर बने अनोखे ग्लास फ्लोर और व्यू प्वाइंट का लोकार्पण किया

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी गौरवशाली संस्कृति और वसुधैव कुटुम्बकम के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए विश्व कल्याण के लिए प्रयास कर रहा है। हमारी संस्कृति में सबके कल्याण और मानवता से प्रेम करने की बात कही गई है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने युवाओं के हित में उनकी शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। मध्यप्रदेश के चारों महानगरों- भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में इसी प्रकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अगले साल पन्ना मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाएगा। नीट के अभ्यर्थियों को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव पन्ना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 35 लाख से

अधिक हितग्राहियों को लगभग 210 करोड़ रुपए की राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। उन्होंने प्रतीक स्वरूप विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के हितग्राहियों एवं आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को कृषि कल्याण वर्ष के उपलक्ष्य में हल भेंट कर सम्मानित किया गया।

पलायन रूका, अब बुंदेलखंड को समृद्ध बनाएंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की धरती सर्वश्रेष्ठ है। यह महाराज छत्रसाल, वीर आल्हा-ऊदल की धरती है। सौभाग्यशाली व्यक्ति ही ऐसी पुण्य धरा पर आ सकता है। यहां पन्ना में धरती के नीचे हीरा निकलता है, लेकिन धीरे-धीरे पानी की कमी होती गई। लोगों ने पलायन शुरू कर दिया, जिसे हमारी सरकार ने रोका। अब हमारी सरकार ने बुंदेलखंड की समृद्धि के लिए भारतरत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्प के अनुसार अंतर्राज्यीय केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की शुरूआत की है। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ की इस परियोजना के लिए 90 प्रतिशत राशि देने की स्वीकृति प्रदान की। नदी जोड़ो परियोजना किसानों के लिए समृद्धि लेकर आएगी। राज्य सरकार ने तय किया है कि ऐसी परियोजनाओं में किसी की जमीन, मकान और दुकान आती है तो उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड परिदृश्य बदलने वाला है। किसान अपनी जमीन बेचने का विचार मन में न लाएं। खेती के मामले में यह क्षेत्र अब पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेगा।

पन्ना क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ाएगा नया अनोखा ग्लास फ्लोर और व्यू प्वाइंट

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने पन्ना के बृहस्पति कुंड पर 8 करोड़ लागत से सौंदर्यीकरण के अंतर्गत निर्मित ग्लास फ्लोर और व्यू प्वाइंट सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया। पन्ना में निर्मित यह कांच के फ्लोर वाला व्यू प्वाइंट यहां के पर्यटन को बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसे देखने देश-विदेश से लोग आएंगे। भारत के पर्यटकों को भी अन्य देशों में जाने की आवश्यकता नहीं है। यहां के प्राकृतिक जल प्रपात पर्यटन में वैश्विक केंद्र बनने के योग्य हैं।

दो सांदीपनि विद्यालयों की सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुल 184.83 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। इन कार्यों में गुन्नौर और पवई के 74 करोड़ रुपए लागत के 2 सांदीपनि विद्यालय शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांदीपनि विद्यालय देश में सबसे अच्छे विद्यालय हैं। प्रदेश में भव्य सांदीपनि विद्यालय बनाए गए हैं। यह विद्यालय भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता के प्रतीक हैं। सांदीपनि विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और संस्कारों के साथ शिक्षा दी जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में लगभग 10 हजार नए पद मंजूर किए हैं। पिछले साल 8 हजार पदों पर भर्ती की गई। प्रदेश में कुल एक लाख से अधिक शासकीय पदों पर युवाओं को नौकरी के अवसर मिले हैं। सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ना चाहती है।

राजगढ़ में दर्दनाक हादसा

भीलखेड़ी जोड़ के पास अनियंत्रित होकर डेम में गिरी कार, पांच लोगों की मौत

राजगढ़। राजगढ़ जिले में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। शुजालपुर के समीप भीलखेड़ी जोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डेम में जा गिरी। हादसे में कार सवार अरन्या गांव के पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू अभियान चलाकर

कार को डेम से बाहर निकाला गया। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार शुजालपुर की ओर जा रही थी। भीलखेड़ी जोड़ के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद कार सीधे डेम में जा गिरी। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस मृतकों की पहचान और हादसे के सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है।

गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही से पूर्ण हों सभी सेतु निर्माण परियोजनाएं

भोपाल। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग का प्रत्येक निर्माण कार्य केवल सड़क, पुल अथवा फ्लायओवर का निर्माण नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास, जनता की सुविधा और विश्वास की मजबूत नींव है। विभाग का मूल उद्देश्य लोक निर्माण से लोक कल्याण की भावना को साकार करना है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, समयबद्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही ही विभाग की कार्यसंस्कृति का आधार हैं तथा इन्हीं मानकों के अनुरूप प्रत्येक परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री श्री सिंह शुक्रवार को वल्लभ भवन में सेतु निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

एक गुरु-एक वृक्ष अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में 40 हजार से अधिक पौधों का हुआ रोपण

भोपाल। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में आयोजित गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा के अंतर्गत शुक्रवार को 'एक गुरुझएक वृक्ष' अभियान के अंतर्गत प्रदेशभर में 40 हजार से अधिक पौधों का रोपण किया गया।

इसके साथ ही विद्यार्थियों ने अपने गुरुओं के सम्मान में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के निर्माण का संकल्प लिया।

विद्यालय परिसरों एवं आसपास आयोजित पौधरोपण कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विद्यालय परिवार ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। अभियान के माध्यम से गुरु-शिष्य परंपरा के सम्मान के साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश भी प्रभावी रूप से प्रसारित किया गया।

गुरु सम्मान के साथ विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के निर्माण का लिया संकल्प

उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के शासकीय स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन और गुरु-शिष्य परंपरा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं, नैतिक मूल्यों एवं गुरु के प्रति आदर की भावना से जोड़ने के साथ-साथ विद्यालयों में संस्कारयुक्त एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण को भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

जनकल्याण की दिशा में मुख्यमंत्री की पहल रही सफल

41 लाख 16 हजार 739 आवेदनों का हुआ निराकरण

भोपाल। एक ही स्थान पर मध्यप्रदेश के नागरिकों की विभिन्न समस्याओं के त्वरित निराकरण और वंचितों को योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की पहल पर प्रदेश सरकार द्वारा 12 से 18 जून 2026 के मध्य प्रदेश में 726 जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया।

इन शिविरों में विभागों के 110 विषयों से जुड़े 41 लाख 43 हजार 158 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 99% (41 लाख 16 हजार 739) आवेदनों का निराकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। विश्व पर्यावरण एवं अंतरराष्ट्रीय योगदिवस के मध्य जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य आमजन को कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना एक ही स्थान पर जन समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के साथ-साथ वंचितों को केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना था।

12 से 18 जून 2026 के मध्य प्रदेशभर में आयोजित किए गए जनकल्याण शिविर

23 से अधिक विभाग रहे शामिल

इन जनकल्याण शिविरों में 23 से अधिक शासकीय विभाग शामिल हुए। इन शिविरों में कुल 41,43,158 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 41,16,739 आवेदनों का निराकरण किया गया। निराकृत किए गए आवेदनों में 40,77,081 आवेदन स्वीकृत हुए।

शिविरों में यह विभाग रहे शामिल

इन शिविरों में राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विकास, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, वित्त विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, उद्यम विभाग, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग शामिल रहे।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ओरछा हेरिटेज विजन के क्रियान्वयन के लिए स्टेट लेवल कमेटी का गठन

भोपाल। राज्य शासन द्वारा ओरछा हेरिटेज विजन के अनुरूप परियोजनाओं की कॉनफॉर्मिटी सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से हेरिटेज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लानके क्रियान्वयन, वर्तमान एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता स्टेट लेवल कमेटी का गठन किया है।

उल्लेखनीय है कि ओरछा को वर्ष 2027-28 के वर्ल्ड हेरिटेज साइकिल के अंतर्गत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए नोमिनेशन डोजियर का निर्माण कार्य प्रचलन में है। आईकॉमोस द्वारा फरवरी 2027 में प्रीलिमिनरी असेसमेंट के दौरान यह अनुशंसा की गई थी कि संबंधित धरोहर संपदा के मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान और संबंधित क्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन से सुदृढ़ किया जाए।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में अपर मुख्य सचिव संस्कृति, नगरीय विकास एवं आवास, प्रमुख सचिव वन, लोक निर्माण, आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, कलेक्टर निवाड़ी, क्षेत्रीय निदेशक (मध्य क्षेत्र), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (आइएएस) सदस्य होंगे। सचिव पर्यटन को सदस्य-सचिव नामित किया गया है। समिति द्वारा आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित के रूप में विषय विशेषज्ञ एवं सलाहकार नियुक्त किए जा सकते हैं। कमेटी को सभी संबंधित विभागों की प्रचलित एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करना है कि वे हेरिटेज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान के अनुरूप एवं उसके अनुपालन में हों। साथ ही योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश जारी करना, यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप एचआईए अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और उनका ओरछा मास्टर प्लान एवं भावी विकास योजनाओं में समावेशन सुनिश्चित करेगी।

...कार्यों का संपादन करेगी

सभी संबंधित विभागों द्वारा प्रचलित एवं भावी परियोजनाओं के नियोजन, अनुमोदन एवं क्रियान्वयन में ओरछा हेरिटेज टूलकिट को अपनाना एवं उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कार्य समिति द्वारा किया जायेगा। धरोहर एकीकृत प्रबंधन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों के मध्य नीतिगत मार्गदर्शन एवं समन्वय स्थापित करना और ओरछा की सभी परियोजनाओं के डीपीआर निर्माण एवं अनुमोदन प्रक्रिया में हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट को सम्मिलित करना सुनिश्चित करेगी। हेरिटेज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान, हेरिटेज टूलकिट और एचयूएल की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में डीएटीसीसी तथा डीएमओके कार्यों एवं प्रगति की समीक्षा करना जैसे कार्यों का संपादन करेगी।

प्रदेश में महिला सशक्तीकरण योजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार

भोपाल। प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों के सशक्तीकरण तथा संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल की है। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने विभाग के अंतर्गत आने वाले द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों, यानी विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारियों के पदों के पारदर्शी और सुचारू व्यवस्थापन के लिए तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने बताया कि विभाग के लगातार बढ़ते कार्यक्षेत्र और नवीन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए मैदानी अमले की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एकीकृत बाल विकास सेवा और महिला सशक्तिकरण संचालनालय के एकीकरण के बाद भी योजनाओं के दायरे में कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि कई नई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुसार मैदानी अमले प्रभावी उपयोग राज्य सरकार की प्राथमिकता है, जिससे जमीनी स्तर पर पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

नया सेटअप और प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था

मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि प्रशासनिक पुनर्व्यवस्थापन की इस योजना के तहत विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारियों के पदों को संचालनालयों, महिला-बाल संरक्षण संस्थाओं, संभागीय व जिला कार्यालयों, क्षेत्रीय समन्वय कार्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों के सेटअप में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न आयोगों और निगमों में आवश्यकतानुसार कतिपय पदों को प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था भी की जा रही है।

मंत्री सुश्री भूरिया ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पदों के प्रतिस्थापन, प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षण और सेटअप में शामिल करने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जाए। मंत्री सुश्री भूरिया ने विभाग को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए विभागीय भर्ती नियमों की समीक्षा करने तथा विभागीय सेटअप को सुव्यवस्थित करने के भी आदेश दिए हैं। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल विभागीय तालमेल में सुधार होगा, बल्कि मैदानी स्तर पर निगरानी मजबूत होने से कुपोषण नियंत्रण, बाल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के सकारात्मक परिणाम और अधिक प्रभावी ढंग से सामने आएंगे।

संतों की वाणी से बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

गुरू पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होकर संतों का प्राप्त किया आशीर्वाद

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अलौकिक जगत में संतों की वाणी से बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे जीवन में संस्कारों का होना भी बहुत आवश्यक है। देश के सभी तीज-त्यौहार भी सार्थक संदेश के माध्यम से मानव कल्याण का संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को पन्ना प्रवास के दौरान श्री जुगल किशोर मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के कार्यक्रम में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने श्रीधाम वृंदावन से पधारे संत श्री श्री 108 महंत स्वामी किशोरदास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों से आए भक्तगणों का अभिवादन कर संतों के सानिध्य में प्रेरणादायी वक्तव्य का अनुसरण करने की बात कही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पन्ना की पावन धरा वृंदावन का लघु स्वरूप है, इसी तरह बुंदेलखंड के अयोध्या के रूप में ओरछा की मान्यता है। उन्होंने कहा कि गौमाता की सेवा के साथ अलग-अलग धर्म के सभी पर्वों को उत्साह के साथ मनाएं। साथ ही विक्रम सम्वत के आयोजन तथा भगवान श्रीराम और

कृष्ण से जुड़े स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने की बात भी कही। अब प्रदेश के सीएम राइज स्कूल सांदीपनि विद्यालय के नाम से संचालित हैं। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में गीता भवन और पुस्तकालय की स्थापना होगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार वृंदावन ग्राम बनाने की अवधारणा पर भी तेजी से आगे बढ़ रही है। हमें धर्मार्थ से परमार्थ की राह पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

सभी धर्मों के लिये प्रदेश में एक कानून

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब प्रदेश में सभी धर्म के लिए एक कानून होगा। सर्वधर्म समभाव के जरिए प्रदेश तरक्की की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पन्ना में प्रत्येक वर्ष तीन दिवसीय कथा उत्सव का आयोजन होगा तथा पन्ना में संस्कृत विद्यालय खोला जाएगा। पन्ना विधायक और पूर्व मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि पन्ना में संतों का समागम सौभाग्य की बात है। पन्ना विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण का कार्य भी संचालित है। इस अवसर पर सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, राजनगर विधायक श्री अरविन्द पटेरिया, सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नगरवासी एवं भक्तगण उपस्थित रहे।

भगवान श्री जुगल किशोर के किए दर्शन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री जुगल किशोर मंदिर पहुंचकर भगवान श्री जुगल किशोर के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने विधिवत पूजन अर्चन कर प्रदेशवासियों के सुख एवं समृद्धि की कामना की।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।